@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

झारखंड को लूटनेवाले और सेवा करनेवाले के बीच है यह चुनाव : नरेन्द्र मोदी

वर्ष-14, अंक-23 01-15 दिसम्बर, 2019 (पाक्षिक) ₹20

झारखंड का विकास सुनिश्चित करेगी भाजपा

लातेहर (झारखंड) में एक विशाल रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 'आदि महोत्सव 2019' का शुभारंभ करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और साथ में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा व केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता

देहरादून (उत्तराखंड) में भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का स्वागत करते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट

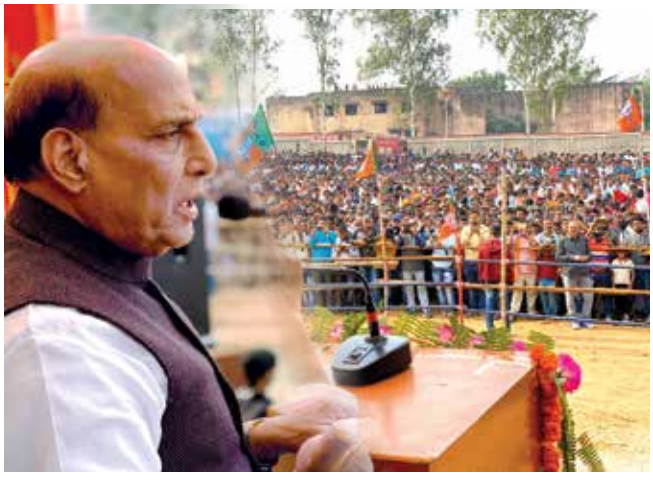

भवनाथपुर (झारखंड) में एक विशाल रैली को संबोधित करते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

नई दिल्ली में '39वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2019' का शुभारंभ करते केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

07 झारखंड को विकसित बनाने के लिए फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार ने देश के मुकुट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर एक राष्ट्र का सपना पूरा किया। अयोध्या में आसमान को छूने वाला भव्य...

वैचारिकी

जनतंत्र और राजनीतिक दल 16

श्रद्धांजलि

नहीं रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी 18

लेख

मूल्यपरक शिक्षा और सतत विकास लक्ष्य 26

साकार हो रहे गरीबों के सपने 28

अन्य

'झारखंड को लूटनेवाले और सेवा करनेवाले के बीच है यह चुनाव' 06

'पार्टी की रीढ़ हैं बूथ कार्यकर्ता' 09

भाजपा ने किया कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन 10

उड़ान/क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत कलबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन 14

उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में मोदी सरकार को दी क्लीन चिट 19

प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही भाजपा 20

'भारत दुनिया की सबसे खुली और निवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था' 22

सरकार ने स्टार्ट-अप, एमएसएमई के लिए पेटेंट व्यवस्था को सरल बनाया है: पीयूष गोयल 24

नितिन गडकरी ने नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया 25

केन्द्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का उद्घाटन किया 30

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिल गेट्स से मुलाकात की 31

'राज्य और केन्द्र प्रतिद्वंद्वी न होकर प्रतिभागी या सहभागी हैं' 32

देश में शांति, एकता और सदभावना के मूल्य सर्वोपरि हैं : नरेन्द्र मोदी 34

08 दिखाएं अंगुली की ताकत, संवारें झारखंड का भविष्य: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 नवंबर को चंदवा हाईस्कूल...

12 भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 18 नवंबर को नई दिल्ली में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ मिलकर भारतीय...

13 कश्मीर में स्थिति सामान्य: अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 20 नवंबर को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है तथा...

15 देवेंद्र फड़णवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अजित पवार बने उपमुख्यमंत्री

भाजपा श्री देवेंद्र फड़णवीस और राकांपा नेता श्री अजित पवार ने 23 नवंबर को महाराष्ट्र के क्रमशः...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

विपक्ष के पास समस्याएं हैं, हमारे पास समाधान हैं। उनके पास सिर्फ झूठे आरोप हैं और हमारे पास अपने काम की रिपोर्ट है। उनके पास कोरी घोषणाएं हैं और हमारे पास विकास का प्रमाण है।

अमित शाह

कांग्रेस ने आदिवासियों के वोट तो लिए, लेकिन उनके कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। आदिवासी मंत्रालय की मांग को भी भाजपा की अटल सरकार ने ही पूरा किया। डीएमएफ के तहत आदिवासियों के कल्याण के लिए 32,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए गए।

जगत प्रकाश नड्डा

झारखंड के डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, हमें यह कार्य जन-जन तक लेकर जाना है एवं विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है।

facebook

प्रदेश के जन-जन को विशेषकर युवा पीढ़ी को मूल कर्तव्यों से परिचित करवाने के लिए 26 नवंबर से बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी की 129वीं जयंती अर्थात् 14 अप्रैल 2020 तक पूरे प्रदेश में मूल कर्तव्य जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

— **मनोहर लाल**

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रदेश के 500 स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम की शुरुआत हुई है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय से इसका शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के 1.90 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। इस क्लासरूम के जरिये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों से लाइव संपर्क किया जा सकता है, शिक्षकों पर नजर रखी जा सकती है। जिन स्कूलों में किसी विषय के शिक्षक नहीं हैं उन विषयों की कक्षाएं भी वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से नियमित रूप से संचालित की जा सकेंगी।

— **त्रिवेन्द्र सिंह रावत**

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में हिमाचल को देशभर में अव्वल बनाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेश को स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। यह समस्त प्रदेशवासियों के लिए हर्ष एवं गौरवान्वित करने वाला विषय है।

— **जयराम ठाकुर**

'कमल संदेश' की ओर से
सुधी पाठकों को
विवाह पंचमी (01 दिसम्बर)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

कांग्रेस अविलंब देश से माफी मांगें

कांग्रेस की झूठ, फरेब और धोखाधड़ी की राजनीति हर दिन बेनकाब हो रही है। राफेल पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कांग्रेस की दुष्प्रचार की राजनीति को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि लोकसभा चुनावों में जिस झूठ के आधार पर कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार कर रही थी, उसे जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से यह और भी स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता इतनी परिपक्व हो चुकी है कि कांग्रेस के झांसे में अब नहीं आ सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राहुल गांधी की क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए ठीक ही उन्हें भविष्य में सावधान रहने के लिये चेताया है। जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी ने एक आधारहीन विषय को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, वह न केवल निंदनीय एवं सिद्धांतहीन है, बल्कि इस तरह के दुष्प्रचार स्वस्थ लोकतंत्र के लिये घातक भी है। आधारहीन दुष्प्रचार को देश की जनता की अदालत में खारिज तो किया ही गया, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में भी अब खारिज हो चुका है। कांग्रेस एवं श्री राहुल गांधी को अविलंब पूरे राष्ट्र से देश को गुमराह करने के लिये माफी मांगनी चाहिए। इस बात की गंभीरता और भी अधिक बढ़ जाती है जब यह प्रमाणित होता है कि यह मात्र कांग्रेस का चुनावी हथकंडा ही नहीं था, बल्कि देश की सुरक्षा के साथ एक भयानक खिलवाड़ था।

पिछले पांच वर्षों में देश ने न केवल ऐसी सरकार देखी है जो कार्य करती है, लक्ष्य सिद्ध करती है तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजना को पहुंचाती है, बल्कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी देखा है जो आतंकवाद को 'सर्जिकल स्ट्राइक' से जवाब देता है, धारा 370 पर निर्णायक कदम उठाता है और दशकों से चली आ रही समस्याओं के निवारण का मार्ग प्रशस्त करता है।

कांग्रेस आज के दौर में जिस सत्तालोलुप राजनीति में लिप्त है उससे वह स्वयं ही सिद्धांतहीन, झूठ, फरेब एवं धोखाधड़ी की राजनीति के दलदल में फंस चुकी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि चुनावों में लगातार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद भी वह आत्मावलोकन करने से इंकार कर रही है। कांग्रेस की जनविरोधी तथा आधारहीन दुष्प्रचार की राजनीति का आधार उसकी झूठ, फरेब और धोखाधड़ी की राजनीति ही रही है। कांग्रेस को अविलंब देश से माफी मांगनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी ने देश के पूरे राजनैतिक परिदृश्य को बदल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं करिश्माई नेतृत्व में सत्ता-केंद्रित राजनीति अब विकास एवं सुशासन के माध्यम से सेवा–केंद्रित राजनीति बन गई है। आज के युग में जब राजनीति का मानदंड 'परफॉर्मेंस एवं सुशासन एवं विकास' बन गया है, तब कांग्रेस स्वयं को इस वातावरण में हाशिये पर पा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को एक नई दिशा, ऊर्जा एवं दृष्टि दी है साथ ही, हर लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता एवं राजनैतिक दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई है।

पिछले पांच वर्षों में देश ने न केवल ऐसी सरकार देखी है जो कार्य करती है, लक्ष्य सिद्ध करती है तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजना को पहुंचाती है, बल्कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भी देखा है जो आतंकवाद को 'सर्जिकल स्ट्राइक' से जवाब देता है, धारा 370 पर निर्णायक कदम उठाता है और दशकों से चली आ रही समस्याओं के निवारण का मार्ग प्रशस्त करता है।

आज राष्ट्र 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है तथा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूते हुए सुशासन एवं विकास के हर मानदंड पर खरा उतर रहा है। कांग्रेस झूठ दुष्प्रचार, सिद्धांतहीन एवं अवसरवादी राजनीति के बल पर स्वयं को बचा नहीं सकती। इस झूठ, फरेब एवं धोखाधड़ी की राजनीति से अब जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। जनता का विश्वास यदि जीतना है तो स्वयं को अनवरत मां भारती की सेवा में समर्पित करना पड़ेगा, जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं करिश्माई नेतृत्व में भाजपा के कोटि–कोटि कार्यकर्ताओं ने स्वयं को समर्पित कर रखा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

झारखंड को लूटनेवाले और सेवा करनेवाले के बीच है यह चुनाव : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव के निमित्त डालटनगंज में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा- नीलांबर पीतांबर की धरती पर आइल रउआ सबके प्रणाम। वंशीधर की धरती पर सबको राम-राम।

श्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों की पीड़ा समझते हुए अलग झारखंड बनाया। अलग जनजातीय मंत्रालय बनाया। पिछड़ों के लिए ओबीसी आयोग को भाजपा सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया। यह भाजपा की सरकार है, सामान्य वर्ग को हमने 10 फीसद आरक्षण दिया। 'सबका साथ-सबका विकास' के प्रति झारखंड के हर वोटर को आश्वस्त करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि रघुवर दास सरकार ने सबके लिए काम किया। 30 नवंबर को सिर्फ एक बात याद रखें। कमल का फूल पर बटन दबाएं और पांच साल तक आपके लिए समर्पित सरकार चलाने का मौका दें।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वे पालते रहे। जानबूझकर इसे 70 साल से लटकाकर रखा। भाजपा ने इसके समाधान का वादा किया था, जिसे पूरा किया। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या का विवाद भी इन लोगों ने दशकों से लटकाया हुआ था। कांग्रेस चाहती तो समाधान निकाल सकती थी, कांग्रेस ने वोट बैंक के फेर में अयोध्या को लटकाकर रखा। कांग्रेस ने दरार नहीं दीवार बना दी। 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के लिए हम समर्पित हैं। एकता के मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। रामजन्मभूमि विवाद अब हल हो गया है। सबको आनंद हो रहा है। भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। एक-एक आदमी की मर्यादा हमारी प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ रेवड़ियां बांटनी जानती है। उनके पास समस्या है। हमारे पास समाधान है। उनके पास आरोप है, हमारे पास रिपोर्ट है। पीएम ने कहा कि बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उनको लगता है कि किसान समृद्ध होंगे तो मोदी का जय-जयकार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड को लूटनेवाले और सेवा करनेवाले के बीच यह चुनाव है। वोट डालने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है कि किसने काम किया, किस मंशा से किया। भाजपा ने जो वादे किए, जो एलान किए हम जमीन पर उतार रहे हैं।

कांग्रेस सिर्फ रेवड़ियां बांटनी जानती है। उनके पास समस्या है। हमारे पास समाधान है। उनके पास आरोप है, हमारे पास रिपोर्ट है।

उन्होंने कहा कि दूसरी सरकारें आएंगी तो वह केंद्र की योजनाओं को लागू करने में आनाकानी करेगी। झारखंड के लिए गौरव की बात है कि उसने आयुष्मान भारत की लांचिंग कर पूरे देश को दिशा दी। डबल इंजन की सरकार में केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा लोगों को अधिक मिलता है। उज्ज्वला योजना से देश के 8 करोड़ लोगों को लाभ मिला। झारखंड के 37 लाख लोगों को दूसरा सिलिंडर मुफ्त मिला। यही डबल फायदा है। पीएम किसान के साथ ही सीएम किसान आशीर्वाद योजना के जरिये डबल इंजन की सरकार ने आपके घर तक लाभ पहुंचाया। इससे विकास में निरंतरता होती है।

उन्होंने कहा कि झारखंड युवा अवस्था में है। इस दौरान यहां जो दिशा मिलेगी, उसका राज्य के भविष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बीते पांच वर्षों में यहां की भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय के पांच बड़े काम किए। सम्मान, सुरक्षा पर बड़े काम हुए। भाजपा ने झारखंड में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दिन-रात काम किया। भाजपा ने समाज के हर आदमी का गौरव बढ़ाया। नक्सलवाद और अपराध से मुक्ति के लिए बेहतर प्रयास किया। आप याद कीजिए पांच साल पहले क्या स्थिति थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां का एक-एक बच्चा कमल निशान के साथ खड़ा हैं। ■

झारखंड को विकसित बनाने के लिए फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार ने देश के मुकुट जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर एक राष्ट्र का सपना पूरा किया। अयोध्या में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देकर भगवान श्रीराम का मान बढ़ाया है। झारखंड के मनिका और लोहरदगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने मतदाताओं से झारखंड विधानसभा चुनाव में कमल के निशान पर बटन दबाने का आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड को विकसित बनाने के लिए फिर से पूर्ण बहमत की सरकार बनाएं। उन्होंने जनता से जुड़ते हुए कहा कि सब मिलकर भाजपा के प्रत्याशी को जिताएं।

श्री शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के आदिवासी समाज के लिए भाजपा ने खुले दिल से काम किया है। रघुवर दासजी के नेतृत्व में झारखंड नक्सल मुक्त हुआ है। मैं भरोसा देता हूं कि भाजपा सरकार बनने के बाद पिछड़ा समाज को आरक्षण बढ़ाने के लिए एक कमिटी बनाएगी। मोदीजी ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। नरेन्द्र मोदीजी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। पहले हमले होते थे तो तब के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। धारा 370 को हटाने का काम किया। 35 ए को समाप्त करने का काम कर कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। कांग्रेस ने झारखंड को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बटन इतनी जोर से दबाएं कि पीड़ा इटली में सुनाई दे। झारखंड का विकास भाजपा का उद्देश्य है। तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाएं।

पहले हमले होते थे तो तब के प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं।

श्री शाह ने कहा कि यहां एक ऐसी सरकार बनाएं कि जिसे जंग न लगे। झारखंड की जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। बचे हुए काम पांच साल में पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासी और पिछड़ों के लिए कई काम किए हैं। लोहरदगा के शत प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। 31 लाख युवाओं को 11 हजार करोड़ रुपये का ऋण मुद्रा लोन के तहत देने का काम किया। 31 लाख से ज्यादा परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। 35 लाख घरों में शौचालय बनाने का काम किया गया।

श्री शाह ने कहा कि झारखंड में फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाएं। सबसे विकसित राज्य झारखंड को बनाएंगे। झारखंड को राज्य बनाने में कांग्रेस ने बाधा बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने झारखंड के लिए क्या किया। हेमंत सोरेन बताएं उन्होंने क्या किया। मोदी जी ने झारखंड में विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने एक गरीब मजदूर को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोहरदगा में यह पहली चुनावी सभा है। साल 2014 में भी यहां से शुरुआत हुई थी। तब पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। श्री शाह ने संबोधत के साथ भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, बुधु भगत सहित को नमन किया। उन्होंने पांडेय गणपत राय के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद किया, साथ ही टाना भगत के योगदान को भी नमन किया।

लोहरदगा में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने 2014 में जनता से पूर्ण विकास का वादा किया था। भाजपा ने एक मजबूत सरकार दी। पांच साल से जनता को एक मजबूत सरकार देने का काम किया। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने किसी की सुध नहीं ली। भाजपा ने लोक कल्याणकारी योजना को लागू करने का काम किया। श्री दास ने कहा कि सरकार ने कई योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाया। उज्ज्वला एक बेहतरीन योजना है। आवास योजना, मछुवारा आवास भी मिल रहा है। 2022 तक कोई गरीब बेघर नहीं रहेगा। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। स्थानीय नीति के नाम पर राजनीति की गई थी। हमने यहां के लोगों को उनका अधिकार दिया। शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। आदिम जनजाति के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। ■

दिखाएं अंगुली की ताकत, संवारें झारखंड का भविष्यः जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 नवंबर को चंदवा हाईस्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी अंगुली में बड़ी ताकत है। जैसे पिछले लोकसभा में 14 में से 12 सीटें जीताकर आपने बड़ी ताकत दी। 05 अगस्त, 2019 को आपके अंगुली के ताकत के कारण ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35 (ए) हटाया गया। उन्होंने कहा कि राजनीति किसी को उठाना या बैठाना नहीं होता है, बल्कि राजनीति आपके अधिकारों का सही प्रयोग कर देश व प्रदेश को आगे ले जाना होता है। अच्छी बहुमत की सरकार आएगी तो विकास के कार्य होंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि सवाल किसी को जीताने या रघुवर दासजी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का नहीं, बस सवाल अगले पांच साल झारखंड का भविष्य उज्जवल बनाने का है। राज्य का भविष्य किसके हाथ में दिया जाए, यह मनन करने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता देखना है तो पीछे का रास्ता भी देख लेना चाहिए। अतीत को न भूलें। पीछे क्या गुजरा है, उसे हमेशा याद रखें, आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। झारखंड अतीत में राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था, जिसके कारण या प्रदेश काफी पीछे चला गया था। रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार में स्थिरता आई और विकास हुआ।

झारखंड अतीत में राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था, जिसके कारण या प्रदेश काफी पीछे चला गया था। रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार में स्थिरता आई और विकास हुआ।

श्री नड्डा ने कहा कि पांच साल पहले नक्सलियों का तांडव हो रहा था। लोग दिन में रोड पर नहीं निकल पाते थे। आज परिस्थितियां बदली हैं। अब मध्यरात्रि भी लोग बेखौफ घूम रहे हैं। नक्सलवाद खात्मे की ओर है। जहां के नेता दागदार होते रहे, आज वहीं बेदाग सरकार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 370 सिर्फ धारा नहीं है। 70 साल से यहां दुश्मनों की नजर थी। यहां देश के 106 कानून नहीं चलते थे। अब संविधान की दृष्टि से भी भारत एक हो गया है। जम्मू कश्मीर में तीन परिवार हलवा खाकर राजनीति करते थे। बैंक की जांच शुरू हो चुकी है। 40 साल तक जिसने लूटने का काम किया, उनकी जगह जेल में होगी। इनकी पोल खुलने लगी है। मोदी एवं रघुवर सरकार ने किसान का सम्मान बढ़ाया। डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला, किसानों को ताकत मिली। मंदी को भी खत्म किया। पूरी दुनिया में भारत का डंका प्रधानमंत्री की वजह से बज रहा है। वैसे ही झारखंड का डंका भी बजाएं।

उधर, चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भाजपा की सरकार आदिवासियों के हित के लिए कई योजनाएं चलाकर लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। लातेहार जिले में आदिवासी बच्चों के लिए दो आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गरीब आदिवासियों के बच्चों शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। भाजपा सरकार जिस तेजी से प्रदेश में विकास कर रही है। जनता का आशीर्वाद पुनः मिला तो विकास की गति को और तेज किया जाएगा। ■

'पार्टी की रीढ़ हैं बूथ कार्यकर्ता'

सत्ता का उद्गम बूथ कार्यकर्ता है। मैं देवभूमि और देवतुल्य बूथ पदाधिकारियों को नमस्कार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि 2022 के विस चुनाव में पूर्व से मजबूत होकर जीत दर्ज करेंगे। उक्त बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने देहरादून में आयोजित बूथ सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। इससे पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहली बार देहरादून आने पर श्री जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया।

गत 15 नवंबर को सुभाष रोड स्थित एक बैंक्वेट हाल में बूथ सम्मेलन का शुभारंभ सर्वश्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट एवं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्जवलित कर किया। श्री नड्डा ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहाड़ के लोगों की जीवन शैली देवतुल्य होती है इसलिए वे समाज को दृष्टि व दिशा देने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा के 385 सांसद, 1451 विधायक और 15 राज्यों में सरकार है। भाजपा आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, महज 54 दिनों के सदस्यता अभियान में सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गई। उत्तराखंड में भी 11 लाख से बढ़कर 17 लाख सदस्य हो गए। यह सब बूथ कार्यकर्ता की मेहनत से ही संभव हो सका।

श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं को समझाने वाले लहजे में कहा कि राजनीति में दो कार्यकर्ता होते हैं दूरगामी और तात्कालिक। तात्कालिक में छोटे इरादे और छोटे लक्ष्य देखे जाते हैं जबकि दूरगामी में पार्टी और देश की सेवा देखी जाती है। बूथ कार्यकर्ता नजदीक का चश्मा उतारकर दूर का पहन ले। ध्यान रखे कि उनकी उंगली से दबाने से कोई नेता नहीं, बल्कि देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। नेशन फर्स्ट-पार्टी सेकेंड कहने से नहीं करने से होता है इसलिए मजबूत सरकार बनाने में योगदान दे ताकि देश मजबूत हो। उन्होंने कहा कि राजनीति में बाई च्वाइस, बाई एक्सीडेंट, बाई चांस आते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा है कि वे सब भाजपा में ही आए। भाजपा में अब सिर्फ इन कमिंग ही इन कमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। यह बूथ कार्यकर्ताओं की ही ताकत का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीति ही है कि सऊदी अरब और ईरान, अमेरिका और चीन दोनों भारत के मित्र हैं। इसी तरह श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी प्रदेश में पारदर्शी सरकार बनाई है। यहां विकास कार्यों में तेजी आई है, 17 लाख परिवारों को आयुष्मान से जोड़ा यही डबल इंजन है। अंत में कार्यक्रम स्थल में मौजूद कार्यकर्ताओं से भाजपा की विचारधारा से जुड़कर आगे बढ़ने पर जोर दिया।

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली के कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पांच 'क' कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कोष और कार्यालय से चलती है। अब भाजपा के हर जिले में कार्यालय है। इस कार्यालय में कांफ्रेंस हाल, मिनी मीटिंग हाल, कंप्यूटराइज्ड आफिस होगा। जो पार्टी कार्यकर्ताओं की सभी दस्तावेजों की भी देखभाल करेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि किसी भवन की मजबूती उसकी मजबूत नींव पर निर्भर करती है। बूथ सदस्यों की बदौलत छह लाख नए सदस्य जुड़कर कुल संख्या 11 से 17 लाख हो गई। बूथ कार्यकर्ताओं के दम पर ही विस चुनाव में चार फीसदी वोट प्रतिशत बढ़ा। 11 जिपं अध्यक्ष इनमें नौ पर महिलाएं हैं। जब महिलाएं आर्थिक सशक्त होंगी तो प्रदेश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 21 से 30 साल के क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य जीते। कई ब्लॉक प्रमुख बने इस तरह उत्तराखंड की राजनीति आज जवान हो गई। यह जवान पीढ़ी प्रदेश के विकास को धार देगी।

भाजपा पांच 'क' कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कोष और कार्यालय से चलती है।

प्रदेश प्रभारी श्री श्याम जाजू ने भाजपा कार्यालय के सभागार को स्व. प्रकाश पंत सभागार का नाम देने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के एक संत ने उनसे कहा कि लोस चुनाव में दिए वोट की स्याही का धब्बा नहीं हटा और सरकार ने 370 का धब्बा हटा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की बदौलत ही राम मंदिर, करतारपुर कोरिडोर में दर्शन करने श्रद्धालु जा रहे हैं, यह तभी संभव है जब मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार बूथ कार्यकर्ताओं ने ही दी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री अजय भट्ट ने कहा कि पार्टी की रीढ़ बूथ कार्यकर्ता है, बूथ ही असली भाजपा है। उन्होंने कहा कि पहले दबिश जाने पर पुलिस फरियादी से खर्च मांगती थी अब ऐसा नहीं है। हर थाने को बजट दिया गया है। श्री भट्ट ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही बिना अधिकारियों के पास जाए घर-घर दुकान-दुकान जाकर 25 करोड़ का कोष जुटा दिया, जो कि एक उपलब्धि है। ■

भाजपा ने किया कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन

राहुल गांधी का झूठ उजागर, मांगें देश से माफी

भारतीय जनता पार्टी ने राफेल मुद्दे पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के आलोक में 16 नवंबर को देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी एवं श्री राहुल गांधी से उनके झूठ के लिए माफीनामे की मांग की।

राफेल पर कांग्रेस के झूठ के खिलाफ देश के हर जिले में धरना-प्रदर्शन की शुरुआत 15 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई थी और देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रदर्शन किया और राहुल गाधी से माफी की मांग की।

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह ने भुबनेश्वर, ओडिशा में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला तो मुंबई महाराष्ट्र में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। पटना में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल ने धरना-प्रदर्शन में भाग लेकर कांग्रेस की पोल खोली तो लखनऊ में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधायक सुरेश तिवारी, विधायक सुरेश श्रीवास्तव और महानगर एवं जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विशाल प्रदर्शन किया। जयपुर में विशाल संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया और श्री राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। शिमला, चंडीगढ़, वाराणसी से लेकर कोलकाता, भोपाल और तिरुअनंतपुरम तक भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ धरना दिया और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। दिल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी और वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विजय गोयल ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और कांग्रेस पार्टी एवं राहुल गांधी के झूठ को जनता के सामने उजागर किया।

श्री राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि देश के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने लगातार झूठ बोलते हुए देश के लोकप्रिय एवं ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया और विश्व पटल पर भारतवर्ष को बदनाम करने की

शर्मनाक कोशिश की, लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद कांग्रेस का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है।

ज्ञात हो कि 14 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च अदालत ने राफेल मुद्दे पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे पहले दिसंबर 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को सही ठहराया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने डील की निर्णय प्रक्रिया, कीमत और ऑफसेट पार्टनर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल की थी और स्पष्ट कहा था कि राफेल डील में कोई अनियमितता नहीं हुई है। इस निर्णय से एक बार पुनः यह स्पष्ट हुआ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं : जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 14 नवंबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी राफेल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करने के देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करती है। श्री नड्डा ने कहा कि इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस बार भी सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह सिद्ध हो गया है कि झूठ के पांव नहीं होते और विजय हमेशा सत्य की ही होती है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर देश के लोकप्रिय और ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की झूठी और शर्मनाक बयानबाजी पर दायर अवमानना याचिका पर निर्णय देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझ कर बार-बार ऐसे बयान दिए और अदालत को राजनीति में घसीटा। कोर्ट ने राहुल गांधी से भविष्य में बयानबाजी में सतर्कता बरतने को भी कहा। चूंकि सजा से बचने के लिए राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग ली थी और कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार कर ली, इसलिए राहुल गांधी सजा से बच गए अन्यथा उन पर इस बयानबाजी को लेकर भी कार्रवाई होती। सड़क से संसद तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील मामले पर देश को गुमराह करने की भरसक कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहती है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। राहुल गांधी को इसके लिए देश से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। काश! राहुल गांधी देश में होते और जनता से माफी मागंते!

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर देश के लोकप्रिय और ईमानदार सुप्रीम कोर्ट में राफेल सौदे को लेकर चार अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी और इसमें मुख्यतः तीन विषयों निर्णय प्रक्रिया, डील की कीमत और ऑफसेट पार्टनर के चुनाव पर सवाल उठाये गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट फैसला दिया कि इसमें जांच की कोई जरूरत नहीं है। आजादी के बाद एक कोरे झूठ के आधार पर देश की जनता को गुमराह करने का इतना बड़ा प्रयास पहले कभी नहीं हुआ। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह दुष्प्रयास देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किया गया है। कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को फटकार इस बात का सबूत है।

राहुल गांधी और कांग्रेस एंड कंपनी द्वारा जान-बूझ कर लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और देश की छवि धूमिल करने के लिए किया गया एक कुत्सित प्रयास भर था और कुछ नहीं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। 2007 से

2014 तक देश की रक्षा जरूरतों से संबंधित सभी मामलों को लटका कर कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का नाम लेकर देश के लोकप्रिय और ईमानदार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने राफेल डील पर एक के बाद एक कई झूठ बोले। राफेल डील की कीमत को लेकर झूठ बोला, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति को कोट करते हुए झूठ बोला, डील की प्रक्रिया को लेकर झूठ बोला, ऑफसेट पार्टनर के चुनाव को लेकर झूठ बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के एक-एक झूठ का पर्दाफ़ाश हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का हर समय अपमान ही किया है चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, सीएजी हो, चुनाव आयोग हो या फिर अन्य संवैधानिक पदों की गरिमा। ■

भारतीय पोषण कृषि कोष का शुभारंभ

2013 से मातृ मृत्यु दर में 26.9 प्रतिशत की कमी

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 18 नवंबर को नई दिल्ली में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष (बीपीकेके) का शुभारंभ किया। यह कोष बेहतर पोषण परिणामों के लिए भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा।

श्रीमति ईरानी ने इस अवसर पर कहा कि यह अपने आप में एक अनोखा अवसर है जब देश को पोषण के मामले में सशक्त बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी, किसानों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक मंच पर आयी है।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सतत जारी रहने वाली हरित क्रांति के उस संदेश के अनुरूप है जिसके जरिए देश के नागरिकों के पोषक आहार की जरुरतों तथा देश में फसल उगाए जाने के तरीकों और कृषि उत्पादन के बीच सामंजस्य लाया जा सके।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने जल शक्ति के नाम से एक अलग मंत्रालय बनाया है, जो अब देश के हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल सितंबर में पोषण माह मनाया गया था और एक महीने में देश भर में 36 मिलियन पोषण संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई थीं।

उन्होंने कहा कि मजदूरी के नुकसान की भरपाई करके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ 10 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंचाया गया जिससे 2013 से मातृ मृत्यु दर में 26.9 प्रतिशत की कमी आई।

श्रीमती ईरानी ने कहा कि वह उन 1.3 मिलियन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और राज्यों की ऐसी ऐजेंसियों को धन्यवाद देना चाहती हैं जो पौष्टिक लक्ष्यों को जीवंत बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन आंगनवाड़ी सहायकों और राज्य की एजेंसियों ने 85 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच बनाई है और उन्हें डैशबोर्ड पर दैनिक अपडेट के माध्यम से सरकार से जोड़ा है।

उन्होंने कहा कि भारत को सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए अब संचार के वैज्ञानिक तरीकों को कार्यान्वयन विज्ञान के साथ जोड़ना होगा, ताकि स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल के साथ ही पोषण भी राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडे में शामिल हो सके।

बिल गेट्स ने कहा कि भारत में अगर कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन करना चाहेगा तो वह महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का निराकरण देश के विकास में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा और उसे सतत विकाल लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा।

उन्होंने बताया कि फाउंडेशन को देश में कुपोषण की चुनौती से निबटने के लिए एक सतत पोषण कार्यक्रम बनाने में भारत सरकार, डब्ल्यूसीडी और अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने में खुशी होगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम एस स्वामिनाथन ने कहा कि भारत को पोषण के मामले में सुरक्षित बनाने के लिए पांच सूत्री कार्य योजना लागू करनी होगी जिसमें:

- महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए कैलरी से भरपूर आहार सुनिश्चित करना,
- महिलाओं और बच्चों में भुखमरी खत्म करने के लिए भोजन में समुचित मात्रा में दालों के रूप में प्रोटीन का शामिल किया जाना सुनिश्चित करना
- विटामिन ए, विटामिन बी, आयरन तथा जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रीएंट की कमी की वजह से होने वाली भूख को खत्म करना
- स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना
- 100 दिन से कम आयु के बच्चों वाले गांवों में महिलाओं को पोषण के बारे में जागरुक बनाना शामिल हो।

डॉ. स्वामिनाथन ने कहा कि बच्चों में पोषक तत्वों की कमी न केवल उनके शारीरिक विकास को अवरुद्ध करती है, बल्कि उसके मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। उन्होंने भुखमरी से निबटने के लिए मंत्रालय से सामुदायिक स्तर पर ऐसे लोगों का समूह बनाने का आग्रह किया, जिन्हें इस पांच सूत्रीय कार्यक्रम का पालन करते हुए महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बीच भुखमरी की समस्या से निबटने के लिए भलिभांति प्रशिक्षित किया जा सके।

इस कार्यक्रम में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी के साथ कृषि, मानव संसाधन विकास, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, यूनीसेफ और विश्व बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक समाज के सदस्य मौजूद थे। ■

कश्मीर में स्थिति सामान्य: अमित शाह

विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 20 नवंबर को राज्यसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पुलिस की गोली से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा उपयुक्त स्थिति पाए जाने के बाद वहां जल्द ही इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी।

प्रश्नकाल के दौरान श्री शाह ने कश्मीर के हालात के बारे में पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर में, विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद पुलिस की गोलीबारी में किसी की जान नहीं गई।

उच्च सदन में गृह मंत्री ने कहा ''वहां स्थिति हमेशा से ही सामान्य है। दुनिया भर में कई तरह की बातें चल रही हैं। वहां स्थिति पूरी तरह सामान्य है। पांच अगस्त के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। हालांकि कई लोगों को आशंका थी कि वहां खूनखराबा होगा तथा लोगों की जान जा सकती है।" श्री शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी समाचार पत्रों का प्रकाशन हो

रहा है और टीवी चैनल काम कर रहे हैं तथा अखबारों के वितरण में कोई कमी नहीं आई है। ■

सड़क सुरक्षा उपायों से 2010-2018 के दौरान दुर्घटनाओं में कमी

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं- 2018' जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2010 तक दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष दर वर्ष मामूली उतार-चढ़ाव के साथ वे कुछ हद तक स्थिर हो गए। इसके अलावा, 2010-2018 की अवधि में दुर्घटनाओं के साथ-साथ दुर्घटनाओं की वार्षिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आई और ऑटोमोबाइल के विकास की अधिक दर के बावजूद पिछले दशकों की तुलना में कम थी।

राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें कुल सड़क नेटवर्क का 1.94 प्रतिशत शामिल है, कुल सड़क दुर्घटनाओं के 30.2 प्रतिशत और 2018 में 35.7 प्रतिशत मौतों का कारण है। राज्य के राजमार्गों में सड़क की लंबाई का 2.97 प्रतिशत हिस्सा 25.2 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 26.8 प्रतिशत मृत्यु का कारण है। अन्य सड़कें, जो कुल सड़कों का लगभग 95.1 प्रतिशत हैं, क्रमशः 45 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 38 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार थीं।

सड़क उपयोगकर्ता की श्रेणी के द्वारा दुर्घटना संबंधी मौतों के संदर्भ में पैदल चलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत थी, साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत थी और दोपहिया वाहनों की संख्या 36.5 प्रतिशत थी। साथ में ये श्रेणियां दुर्घटना संबंधी मौतों का 53.9 प्रतिशत है और वैश्विक रुझानों के अनुरूप सबसे असुरक्षित श्रेणियां हैं।

2018 के दौरान पिछले दो वर्षों की तरह, 18 से 45 वर्ष के युवा वयस्क लगभग 69.6 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं के शिकार बने। कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 18 वर्ष से 60 वर्ष आयुवर्ग के कामकाजी आयु समूह की हिस्सेदारी 84.7 प्रतिशत थी।

2018 में हिट एंड रन के मामलों में 18.9 प्रतिशत मौतें हुई थीं, जबकि 2017 में यह 17.5 प्रतिशत थी। 2018 में लगभग 56 प्रतिशत व्यक्तियों की मौत आमने-सामने टक्कर और उसके बाद पीछे से लगी टक्कर के कारण हुई। इस श्रेणी में 2018 में मारे गए व्यक्तियों के संदर्भ में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई थी। ■

उड़ान/क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत कलबुर्गी हवाई अड्डे का उद्घाटन

उड़ान योजना के तहत अब तक 230 मार्गों और 42 हवाई अड्डों का संचालन

कलबुर्गी हवाई अड्डे से 22 नवंबर को बेंगलूरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहली विमान सेवा शुरु हो गई। यह हवाई अड्डा सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान-क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बनाया गया है। इसे 176 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 742 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है।

हवाई अड्डा कलबुर्गी शहर से 13.8 किमी की दूरी पर है और यह वीएफआर/दैनिक संचालन के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है। यहां से प्रति सप्ताह तीन उड़ानें सोमवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित की जाएंगी। यह उड़ान 12:20 बजे केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (केआईए) से प्रस्थान करेगी और दोपहर 1:25 बजे कलबुर्गी पहुंचेगी। वापसी में यह कालबुर्गी से 1:55 बजे रवाना होगी और 3 बजे केम्पेगौड़ा पहुंचेगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कलबुर्गी हवाई अड्डे को विकसित करने का काम इसलिए किया है क्योंकि यह राज्य के उसके मुख्यालयों और अन्य वाणिज्यिक केंद्रों के साथ उत्तरी कर्नाटक के लिए सीधे संपर्क का मार्ग प्रशस्त करेगा। कलबुर्गी हवाई अड्डा बुद्ध विहार, शरणबसवेश्वर मंदिर, ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह और गुलबर्गा किले सहित पर्यटन स्थलों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा।

कलबुर्गी हवाई अड्डा खुल जाने से राज्य के मूल निवासी बेंगलुरु और देश के अन्य हिस्सों में बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। नवनिर्मित हवाई अड्डा भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की देखरेख में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की दृढ़ता के अनुरूप है, ताकि देश को बेहतर हवाई संपर्क के साथ सक्षम बनाया जा सके।

गौरतलब है कि अब तक उड़ान के तहत 230 मार्गों और 42 हवाई अड्डों का संचालन किया गया है। उड़ान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 700 वायु मार्गों से जोड़ेगा, जो भारत के विमानन क्षेत्र में एक नए क्षेत्रीय संपर्क की नींव रखेंगे। ■

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित

न्यास को अराजनैतिक बनाने का प्रयास

राज्यसभा में 19 नवंबर को जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित हो गया। इसके साथ ही यह विधेयक संसद द्वारा पारित हो गया। लोकसभा 2 अगस्त, 2019 को पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है।

इस विधेयक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को न्यास का स्थायी सदस्य बनाए जाने से संबंधित धारा को हटाकर इसका संचालन करने वाले न्यास को अराजनैतिक बनाने का प्रयास किया गया। विधेयक में यह संशोधन भी किया गया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अथवा जहां विपक्ष का ऐसा कोई नेता नहीं हो, तो ऐसे में सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को न्यास के सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।

विधेयक में यह संशोधन भी किया गया है कि नामित न्यासी को पांच साल की अवधि समाप्त होने से पहले भी केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने इस अवसर पर कहा कि इस वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार की 100वीं बरसी है और इस घटना के 100 साल बीत जाने के बाद आवश्यक है कि जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक को सही मायने में राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। ये संशोधन इस स्मारक को सही मायने में राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। ■

देवेंद्र फड़णवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, अजित पवार बने उपमुख्यमंत्री

भाजपा श्री देवेंद्र फड़णवीस और राकांपा नेता श्री अजित पवार ने 23 नवंबर को महाराष्ट्र के क्रमशः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। गौरतलब है कि राज्य में 12 नवंबर को लगाए राष्ट्रपति शासन को 23 नवंबर को हटा दिया गया।

गठबंधन में राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा और शिवसेना ने 288 सदस्यीय सदन में क्रमशः 105 और 56 सीटें जीती थीं, लेकिन शिवसेना ने भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री पद साझा करने से इनकार करने के बाद उसके साथ अपने तीन दशक पुराने संबंध खत्म कर लिए। दूसरी ओर, चुनाव पूर्व गठबंधन करने वाली कांग्रेस और राकांपा ने क्रमशः 44 और 54 सीटें जीती। श्री फड़णवीस की मुख्यमंत्री पद पर वापसी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुंबई और नवी मुंबई समेत राज्य के कई हिस्सों में मिठाइयां बांटी और ढोल की थाप पर थिरके।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और जे पी नड्डा ने दी बधाई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री देवेंद्र फड़णवीस और श्री अजित पवार को महाराष्ट्र के क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ''देवेंद्र फड़णवीस और अजित पवार को महाराष्ट्र के क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि ये दोनों महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिये काम करेंगे।''

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने भरोसा जताया कि देवेन्द्र फड़णवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के शासन में महाराष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा।

श्री शाह ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्वीट कर श्री फड़णवीस और राकांपा नेता श्री अजित पवार को बधाई दी। श्री शाह ने ट्वीट किया,"देवेंद्र फड़णवीस जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अजित पवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई।" उन्होंने कहा, ''मुझे विश्वास है कि यह सरकार महाराष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति निरंतर कटिबद्ध रहेगी और प्रदेश में प्रगति के नये मापदंड स्थापित करेगी।'

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा ने भी फड़णवीस और अजित पवार को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया,"मैं देवेन्द्र फड़णवीस जी और अजीत पवार जी को महाराष्ट्र के क्रमशः मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बधाई देता हूं। मुझे यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह सरकार महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री फड़णवीस और श्री अजित पवार को महाराष्ट्र के क्रमशः मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। योगी ने ट्वीट कर दोनों को बधाई दी और विश्वास जताया कि फड़णवीस और पवार के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास के रास्ते पर चलेगा। ■

जनतंत्र और राजनीतिक दल

दीनदयाल उपाध्याय

अधिकांश भारतीय जनता जनतांत्रिक जीवन की आकांक्षी है; किंतु इधर अनेक एशियाई देशों में जनतांत्रिक सरकारों की विफलता या उनके दबा दिए जाने के कारण भारत में बहुत से लोग देश में जनतंत्र के भविष्य के बारे में आशंकित हो उठे हैं। आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बिगड़ते जाने के कारण कठिन स्थिति का सफलतापूर्वक सामना कर सकने की जनतंत्र की क्षमता के बारे में भी लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया है। ऐसे अनेक लोग हैं, जो 'जो कुछ अपने पास नहीं है उसके लिए तरसते हैं' और अविवेकपूर्ण ढंग से वैकल्पिक स्वरूपों की सरकार की स्थापना की आकांक्षा करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो जनतंत्र में दृढ़ विश्वास के साथ भारत के वर्तमान जनतांत्रिक ढांचे को ब्रिटिश संसदीय जनतंत्र के बाहरी रूपों का एक घटिया अनुकरण मानते हैं। वे चाहते हैं कि यदि सच्चे जनतंत्र के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था अलग ढंग से गठित की जानी चाहिए।

जनतांत्रिक पद्धति के रूपों और औपचारिकताओं का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो सकता है, परंतु इस पद्धति के सफल होने की आशा करने के पूर्व कतिपय ऐसी अनिवार्यताएं भी हैं, जिनके बारे में गारंटी दी जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन' ने उड़ीसा विधानमंडल के नए भवन का उद्घाटन करते हुए अपने भाषण में इन अनिवार्य पूर्वावश्यकताओं की ओर ठीक ही ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी देश में अनुशासित राजनीतिक दल और निष्ठावान तथा देशभक्त नेतृत्व संसदीय जनतंत्र की सफलता के अपरिहार्य अंग हैं। उन्होंने जनतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र समाचार-माध्यम (प्रेस), स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वच्छ एवं सक्षम प्रशासन को भी आवश्यक बताया।

फिर भी, चूंकि जनतांत्रिक सरकार में अंतिम अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास रहता है, अन्य किसी भी बात से उनका अधिक महत्त्व है, क्योंकि जब तक जनता प्रकट विद्रोह के लिए तैयार न हो, समाचार-पत्र (प्रेस), न्यायपालिका और प्रशासन को अनुचित उपायों से सत्तारूढ़ दल की इच्छाओं के सामने झुकने के लिए विवश किया जा सकता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाचार-पत्रों का मुंह बंद किया जा सकता है, न्यायपालिका के न्यायिक निर्णयों को निष्फल बनाने के लिए विधान में संशोधन कर उसे दुर्बल बनाया जा सकता है और प्रशासन को शीर्षस्थ भ्रष्ट नेताओं द्वारा भ्रष्ट बनाया जा सकता है। इसलिए यदि हम देश के कार्यकलाप में सुधार चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम राजनीतिक दलों की ओर ध्यान देना होगा।

जहां तक भारत के राजनीतिक दलों का संबंध है, उनमें बहुत सी त्रुटियां हैं। इसमें सबसे दोषी सत्तारूढ़ दल (कांग्रेस) है, परंतु अन्य अनेक दलों का आचरण भी कुछ अच्छा नहीं है। आज राजनीतिक दल सैद्धांतिक आधार पर नहीं, वरन् व्यक्तिगत या गुट के आधार पर गठित होते हैं। इस संबंध में डॉ. राधाकृष्णन कहते हैं, 'राजनीति' अंततः साध्य तक पहुंचने का एक साधन है। यह ऐसी व्यवस्था का निरूपण करती है, जिसके द्वारा सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। यदि जनतंत्र केवल यहीं तक अपनी गतिविधियां सीमित रखता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल सत्ता की होड़ में लगे रहें और पद के पीछे दौड़ते रहे तथा राज्य के कार्यों को इस प्रकार छोड़ दें कि वह अस्त-व्यस्त हो जाए तो वह जनतंत्र नाम के लिए भी अच्छा नहीं।" आज राजनीति साधन नहीं रह गई है। वह स्वयं साध्य बन गई है। आज हमारे बीच ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो निश्चित सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से राजनीतिक सत्ता पर ध्यान देने की अपेक्षा केवल सत्ता के लिए होड़ में अधिक व्यस्त हैं। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल जनता को सुसंगठित बनाने और अव्यवस्था में से व्यवस्था का निर्माण करने के स्थान पर वर्तमान अव्यवस्था में

आज राजनीति साधन नहीं रह गई है। वह स्वयं साध्य बन गई है। आज हमारे बीच ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो निश्चित सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से राजनीतिक सत्ता पर ध्यान देने की अपेक्षा केवल सत्ता के लिए होड़ में अधिक व्यस्त हैं।

केवल और वृद्धि करते हैं। अपने पास आने वाले लोगों के दृष्टिकोणों की कोई चिंता न करते हुए वे केवल इस बात की ओर ही ध्यान देते हैं कि उनके अनुयायियों की संख्या बढ़े।

भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को अपने लिए एक दर्शन (सिद्धांत या आदर्श) का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकत्र आने वाले लोगों का समुच्चय मात्र नहीं बनना चाहिए। उनका रूप किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान या ज्वॉइंट स्टॉक कंपनी (Joint Stock Company) से अलग प्रकार का होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि दल का दर्शन केवल उसके घोषणा-पत्र के पृष्ठों तक ही सीमित न रह जाए। सदस्यों को उसे समझना चाहिए और कार्यरूप में परिणत करने के लिए निष्ठापूर्वक जुट जाना चाहिए।

किंतु हर आदर्श, किसी दल को जनतंत्र का युग लाने में समर्थ नहीं बनाएगा। वह आदर्श स्वयं जनतंत्र के आदर्शों और भावनाओं के विपरीत नहीं होना चाहिए। वस्तुतः अनेक देशों में ऐसे लोगों के हाथ से जनतंत्र को बड़ी क्षति उठानी पड़ी है, जिन्होंने जनतंत्र का उपयोग केवल उसे विनष्ट कर देने के लिए किया। कम्युनिस्टों के पास एक विचारधारा है और वे जनतांत्रिक मार्ग के अनुसरण का दावा करते हैं- केवल अंततः जनतंत्र का अंत कर देने के लिए। डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों में- "व्यक्ति के सम्मान और उसकी स्वतंत्रता का सिद्धांत जनतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। मानवता के इतिहास में मनुष्य की स्वतंत्र भावना सारी प्रगतियों का कारण रही है। व्यक्ति को नष्ट कर देने की प्रवृत्ति रखने वाली कोई भी पद्धति अजनतांत्रिक है। विचार-विमर्श, समझा-बुझाकर सहमत करना, परस्पर समाधानकारी समझौता और दो तथा लो, ये जनतांत्रिक मार्ग की युक्तियां हैं।" इसलिए ऐसा कोई भी सिद्धांत, जो लचीला नहीं है तथा जो मानव के सम्मान और स्वातंत्र्य में विश्वास नहीं रखता, वह जनतांत्रिक व्यवस्था के उपयुक्त नहीं होगा। ऐसे दलों को या तो अपने सिद्धांतों को जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप बनाना चाहिए या जनतंत्र की केवल मौखिक सेवा बंद कर देनी चाहिए।

दल के कार्यकर्ताओं में अनुशासन का प्रश्न न केवल दल को पूर्ण स्वस्थ रखने के लिए अपितु सामान्य रूप से जनता के आचरण पर भी उसके प्रभाव की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। मुख्यतः सरकार सुरक्षा और संरक्षा का एक साधन है, न कि विनाश और परिवर्तन का। जनता में विधान के प्रति समादर की भावना उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि विधान का संरक्षक बनने की आकांक्षा रखने वाले दल इस दिशा में स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें । स्व-शासन की भावना और क्षमता जनतंत्र का सार है। यदि राजनीतिक दल स्वयं अपने को शासित नहीं कर सके तो वे समाज में स्व-शासन की इच्छा उत्पन्न करने की आशा कैसे कर सकते हैं? जहां एक ओर समाज के लिए व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की प्रतिभूति (गारंटी) और रक्षा आवश्यक है, वहीं व्यक्ति के लिए भी सर्वसामान्य की इच्छा का स्वेच्छया आदर करना वांछनीय है। यह सहिष्णु भावना जितनी अधिक होगी, राज्य के अदम्य अधिकार उतने ही कम हो जाएंगे। कोई भी दल, जिसके कार्यों का किसी सरकारी विधान द्वारा नियमन नहीं होता अपनी इकाइयों द्वारा स्वेच्छया स्वीकृत निर्णयों के अनुसार चलते हैं। इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि सर्वोत्तम व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सदस्यों के लिए एक आचरण संहिता निर्धारित करें और उसका कड़ाई से पालन करें।

भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को अपने लिए एक दर्शन (सिद्धांत या आदर्श) का क्रमिक विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें कुछ स्वार्थों की पूर्ति के लिए एकत्र आने वाले लोगों का समुच्चय मात्र नहीं बनना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि दल का दर्शन केवल उसके घोषणा-पत्र के पृष्ठों तक ही सीमित न रह जाए।

जनतंत्र में एक से अधिक दलों का होना स्वाभाविक है। ये दल यदि स्वस्थ परंपराओं का विकास करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी-न-किसी प्रकार के पंचशील का अनुसरण करना चाहिए। सैद्धांतिक आधार पर किसी दल से संबंध-विच्छेद को उचित माना जा सकता है, परंतु अन्य आधारों पर दलों द्वारा दल-बदल को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब कोई दल बहुमत में न आए, या उसे अत्यल्प बहुमत प्राप्त हो, तब अन्य दलों से समर्थन पाने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अनुचित साधन अपनाए जाने की संभावना है। यह आवश्यक है कि हम ग्रेट ब्रिटेन की द्विदलीय संसदीय पद्धति से कुछ अलग परंपराएं विकसित करें और अपनाएं। केवल उससे ही देश में स्थिर सरकार रहेगी और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों का अखाड़ा बनने से दलों की रक्षा हो सकेगी।

ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिन पर विचार आवश्यक है। क्या जनतंत्र में विश्वास रखने वाले दल अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करेंगे? सत्ता प्राप्त करने की उत्सुकता और शीघ्रता में उन्हें उस आधार को ही नष्ट नहीं कर देना चाहिए, जिस पर वे खड़े हैं। ■

-ऑर्गनाइज़र, फरवरी 17, 1961 (अंग्रेज़ी से अनूदित)

नहीं रहे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी

(14 जुलाई 1929 - 24 नवंबर 2019)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश चंद्र जोशी नहीं रहे। 24 नवंबर को 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार चल रहे थे। श्री कैलाश जोशी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और उत्कृष्ट व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। अपनी वाणी से लोगों का दिल जीत लेने वाले श्री कैलाश जोशी एक प्रखर वक्ता के साथ प्रशासकीय गुणों से संपन्न थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों, वंचितों के उत्थान और कल्याण के लिए होम कर दिया।

श्री कैलाश जोशी का जन्म 14 जुलाई 1929 को हुआ था। वे 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद ही उसके सदस्य बन गए। वे 1972 से 1977 तक मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रहे। वे 1977 से 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 1980 से 1984 तक मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। वे आठ बार विधानसभा सदस्य रहे और राज्यसभा तथा लोकसभा के भी सदस्य रहे।

श्री जोशी के निधन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि श्री जोशी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुःख हुआ। एक राजनीतिक कार्यकर्ता और ज़मीनी नेता के रूप में श्री जोशी ने मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा, "उनका निधन हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।"

श्री जोशी के निधन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया और दुःख जताया। उन्होंने लिखा, 'कैलाश जोशी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास में एक मजबूत योगदान दिया। उन्होंने मध्य भारत में जनसंघ और भाजपा को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने एक प्रभावी विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से दुःख हुआ। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।

श्री जोशी के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शोक व्यक्त और कहा कि श्री जोशी का मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह अनुभवी कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही जनप्रिय नेता भी थे। उन्होंने कहा, "दुःख की घड़ी में शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना एवं विनम्र श्रद्धांजलि।"

श्री जोशी के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने गहरा शोक व्यक्त किया। श्री शाह ने ट्वीट किया, 'मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। वह एक जमीन से जुड़े नेता थे जो सदैव जनता के हितों के लिए प्रयासरत रहे। मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।"

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने शोक संदेश में कहा, "श्री जोशी जी के निधन से मन अत्यंत दुःखी है। उनका निधन संगठन के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए

ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ॐ शांति।"

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें श्री जोशी जी के निधन का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। वह जमीन से जुड़े नेता थे जो सदैव जनता के हितों के लिए प्रयासरत रहे। राज्य में संगठन विस्तार में उनकी अहम भूमिका रही। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।"

श्री जोशी के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा कि मृदभाषी, सरल, सहज व्यक्तित्व के धनी कैलाश जी का निधन राजनीति क्षेत्र की एक अपूरणीय क्षति है। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री जोशी के निधन पर कहा कि वे राजनीति के संत थे, उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की राजनीति को नई दिशा देने वाले, निर्धन और कमजोर की आवाज़, विनम्र एवं मृदुभाषी राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के अवसान के साथ ही एक युग का अंत हो गया। उन्हें कोटि-कोटि प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। ■

उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे में मोदी सरकार को दी क्लीन चिट

उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार को 14 नवंबर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है। प्रधान न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं।'' पीठ में न्यायमूर्ति श्री एस के कौल और न्यायमूर्ति श्री के एम जोसेफ भी शामिल थे।

उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

उच्चतम न्यायालय ने 14 नवंबर को कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी को राफेल सौदे के सिलसिले में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर फटकार लगाई और उन्हें भविष्य में अधिक सावधानी बरतने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति श्री संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति श्री के एम जोसफ की पीठ ने कहा कि यह 'दुर्भाग्यपूर्ण' है कि राहुल गांधी ने इसकी पुष्टि नहीं की और इस बारे में बार-बार बयान दिये जैसे शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोपों को कोई मंजूरी दे दी थी।

पीठ ने कहा कि यह 'सच्चाई से कोसों दूर था' और 'राजनीतिक परिदृश्य' में इस तरह का महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्तियों को और अधिक सावधान रहना चाहिए। पीठ ने कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिये भाजपा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी की याचिका पर अपने फैसले में यह टिप्पणियां की।

पीठ ने कहा कि गलती स्वीकार करके बिना शर्त क्षमा याचना करने की बजाए कांग्रेस नेता द्वारा 20 पेज के हलफनामे के साथ तमाम दस्तावेज संलग्न करने से मामला और उलझ गया था। न्यायमूर्ति श्री कौल, जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश और अपनी ओर से फैसला लिखा, ने कहा, ''हमें यह इंगित करना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में पारित आदेश के बगैर पुष्टि या अवलोकन के ही अवमाननाकर्ता (गांधी) ने यह बयान देना उचित समझ लिया मानो न्यायालय ने प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके आरोपों पर मुहर लगा दी है, जो सच्चाई से कोसों दूर था।''

शीर्ष अदालत ने कहा, ''यह एक वाक्य या अचानक की गयी टिप्पणी नहीं थी, लेकिन अलग अलग तरीके से यही कहने के लिये बार-बार बयान दिये गये। इसमें संदेह नहीं कि अवमाननाकर्ता को और अधिक सावधान रहना चाहिए था।''

पीठ ने श्री राहुल गांधी के पांच मई के अतिरिक्त हलफनामे, जिसमें उन्होंने बिना शर्त क्षमा याचना की थी, का जिक्र करते हुये कहा कि उनके अधिवक्ता को बहस के दौरान यह सदबुद्धि आयी और इसके बाद एक हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें कहा कि वह शीर्ष अदालत का सर्वोच्च सम्मान करते हैं और उनकी मंशा कभी न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की नहीं थी।

राहुल गांधी ने आठ मई को राफेल फैसले में 'चौकीदार चोर है' की टिप्पणी शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के लिये पीठ से बिना शर्त माफी मांग ली थी। न्यायालय ने श्री राहुल गांधी को इस मामले में उनके पहले के हलफनामे के लिये 30 अप्रैल को फटकार लगायी थी, जिसमे उन्होंने कहा था कि उन्होंने सीधे-सीधे इन टिप्पणियों के लिये अपनी गलती नहीं मानी थी।

पीठ ने कहा, ''हमारा मानना है कि राजनीतिक परिदृश्य में इतने महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों को अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस पर विचार करना राजनीतिक व्यक्ति का काम है कि उनके प्रचार का तरीका क्या होना चाहिए।''

गौरतलब है कि श्री राहुल गांधी ने आठ मई को राफेल फैसले में 'चौकीदार चोर है' की टिप्पणी शीर्ष अदालत के हवाले से कहने के लिये पीठ से बिना शर्त माफी मांग ली थी। न्यायालय ने श्री राहुल गांधी को इस मामले में उनके पहले के हलफनामे के लिये 30 अप्रैल को फटकार लगायी थी, जिसमे उन्होंने कहा था कि उन्होंने सीधे-सीधे इन टिप्पणियों के लिये अपनी गलती नहीं मानी थी। ■

प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही भाजपा

विपुल शर्मा

निर्वाचन आयोग ने आगामी झारखंड विधान सभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए 30 नवंबर से पांच चरणों में मतदान होगा और 23 दिसंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।

राज्य में पांच चरणों में होने वाले चुनाव 30 नवंबर, 07 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर और 20 दिसंबर, 2019 को संपन्न होंगे। वर्तमान 81 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 05 जनवरी, 2020 को समाप्त हो रहा है। राज्य की 81 सीटों में से 09 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 28 अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

साल 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी सहयोगी आजसू के साथ मिलकर 42 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में सरकार बनाई थी। गौरतलब है कि आजसू ने पिछले चुनावों में 5 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इन चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही, जेवीएम (पी) ने 8 और कांग्रेस ने केवल 6 सीटों पर जीत हासिल की।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार विधानसभा चुनावों में भाजपा को 31.26 प्रतिशत और कांग्रेस को 10.46 प्रतिशत वोट हासिल हुए। इन चुनावों में मतदान प्रतिशत में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई और यह 66.42 प्रतिशत रहा।

पार्टी	सीट	वोट प्रतिशत
भारतीय जनता पार्टी	37	31.26%
झारखंड मुक्ति मोर्चा	19	20.4%
आजसू	5	3.68%
जेवीएम (पी)	8	9.99%
कांग्रेस	6	10%

झारखंड पिछली कांग्रेस-झामुमो गठबंधन सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार और राज्य संसाधनों के बेहिसाब दोहन का गवाह बना। खासकर कांग्रेस ने हर तरह से झारखंड राज्य और यहां के लोगों का शोषण किया। वर्तमान विपक्ष को कई वर्षों तक जनता की सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन यह विपक्षी पार्टियां राज्य को एक स्थिर सरकार देने में भी कामयाब नहीं हो सकीं। इसलिए पिछले चुनाव के दौरान राज्य की जनता ने विपक्षी दलों से पूछा कि कांग्रेस-जेएमएम और अन्य विपक्षी दल 70 साल बाद भी बिजली, रसोई गैस, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं मुफ्त इलाज, घर, गरीबों के लिए शौचालय आदि उपलब्ध करवाने में क्यों कामयाब नहीं हुए? कांग्रेस ने आदिवासियों को न केवल धोखा दिया, बल्कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं और अन्य अधिकारों से भी वंचित रखा। इसलिए जनता ने पिछले चुनावों में विपक्षी दलों को बुरी तरह से हराया।

पिछले 5 वर्षों में भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत झारखंड में 10 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जबकि पीएम आवास योजना के तहत 2016-17 में 5.29 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी और राज्य सरकार ने 90 प्रतिशत आवास इकाइयों का काम पूरा कर उन्हें लाभार्थियों को सौंप भी दिया है।

राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को भी प्रभावी ढंग से लागू किया है, जिसे रांची से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। राज्य के 68 लाख परिवारों में से कुल 57 लाख परिवार को इस योजना के साथ जोड़ा जा चुका है और लाभार्थियों को "गोल्डन कार्ड" प्रदान किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से निर्धारित अस्पतालों में यह लोग स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज प्राप्त करने में सक्षम हुए है।

देश में आदिवासियों के कल्याण को महत्व देते हुए मोदी सरकार ने अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय वन अधिनियम (1927) में संशोधन कर इसके एक विवादास्पद प्रस्ताव को वापस ले लिया, जो आदिवासियों खासतौर पर जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए बेहद 'कठोर' प्रावधान माना जा रहा था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा, जिसका उल्लेख उन्होंने पहले भी

किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड गरीब और आदिवासी समुदायों के लिए बड़ी कल्याणकारी योजनाओं का लॉन्च पैड बनने जा रहा है।

केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें, जिन्हें डबल-इंजन सरकार के रूप में भी जाना जाता है, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य विकास कार्यों को लागू करने में बहुत सफल हैं।

ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा के प्रदेश दौरों ने भाजपा के चुनावी अभियान में नई जान फूंक दी है।

श्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनावों की दिशा तय करते हुए कहा कि 'झामुमो नेता हेमंत सोरेन से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने किस पार्टी के साथ गठबंधन किया है, एक ऐसी पार्टी जिसने 70 साल से आदिवासियों को गुमराह किया है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन भ्रष्टाचार और आदिवासियों एवं गरीबों को धोखा देने के लिए हुआ है, यह गठबंधन राज्य के विकास के लिए नहीं हुआ है।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने झारखंड का दौरा किया और यहां एक विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य सरकार और भाजपा का संगठन तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनता इस बार हमें 65 से अधिक सीटों पर विजयी बनाकर आशीर्वाद देगी।"

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और राज्य सरकार के प्रदर्शन के आधार पर लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के लिए आश्वस्त है। केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश में आदिवासियों और अन्य वर्ग के विकास को लेकर प्रतिबद्ध हैं। झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने और विकास की नई राह पर ले जाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा स्वागत किया गया है।

झारखंड चुनाव विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती बनकर सामने आए है, जो गठबंधन कर राज्य में सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रहे है। विपक्षी दलों के सामने चुनौती बहुत अधिक बड़ी है, क्योंकि पांच महीने पहले हुए आम चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने राज्य की 14 में से 12 लोकसभा सीटें पर जीत दर्ज की थी।

ऐसा लगता है कि राज्य का मतदाता इस बार भी भाजपा सरकार को पूरे मनोयोग से समर्थन दे रहा है, ताकि गरीबों के कल्याण के साथ ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों को और तेज किया जा सके। आम लोग यह भी जानते हैं कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो झारखंड को देश के अग्रणी राज्य की सूची में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा कि "भाजपा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है"। ■

भाजपा सरकार की प्रमुख योजनाएं

मुख्यमंत्री कृषि अशीर्वाद योजना: इस योजना के तहत 35 लाख से अधिक लघु और सीमांत किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया गया है।

पीएम उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल: इस योजना के तहत लोग केंद्र सरकार की फ्लैगशिप पीएमयूवाई योजना के तहत प्राप्त गैस सिलेंडर को मुफ्त रिफिल करवाने की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही राज्य सरकार 12 लाख नए एलपीजी कनेक्शन भी देने जा रही है।

सहिया आरोग्य कुंजी योजना: इस योजना के तहत सभी गांवों में जनता को उचित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य कुंजी (मेडिकल किट) उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019: इस योजना के तहत सभी लड़कियों को उनके जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक रु. 30,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी।

झारखंड वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन: झारखंड सरकार ने इस सहायता राशि को रु. 600 से बढ़ाकर रु. 1000 प्रति माह करने का निर्णय लिया है।

झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखें

चरण 1	30 नवंबर
चरण 2	7 दिसंबर
चरण 3	12 दिसंबर
चरण 4	16 दिसंबर
चरण 5	20 दिसंबर
23 दिसंबर को मतगणना	

भारत दुनिया की सबसे खुली और निवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था: नरेन्द्र मोदी

वैश्विक मंदी के बावजूद ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को दी गति

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13-14 नवंबर को ब्राजील के ब्रासिलिया शहर में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे "खुली एवं निवेश के लिए अनुकूल" अर्थव्यवस्था बताते हुए ब्रिक्स देशों की कंपनियों और कारोबारियों से भारत में निवेश करने और वहां मौजूद "असीम" संभावनाओं तथा "अनगिनत" अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

नवाचार हमारे विकास का आधार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 नवंबर को ब्राजील में अन्य सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ ब्रिक्स के ग्यारहवें शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस बार इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय नवाचार युक्त भविष्य के लिए आर्थिक विकास बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि नवाचार अब हमारे विकास का आधार बन चुका है। उन्होंने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर भी जोर दिया।

श्री मोदी ने कहा, 'अब हमें ब्रिक्स की दिशा पर विचार करना है और अगले दस वर्षों में आपसी सहयोग और अधिक प्रभावी होना चाहिए।' उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई क्षेत्रों में सफलता के बावजूद कुछ क्षेत्रों में और प्रयास करने की काफी गुंजाइश है। प्रधानमंत्री ने आपसी व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान देने का आह्वान करते हुए कहा कि यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ब्रिक्स देशों के बीच आपासी व्यापार दुनिया के कुल व्यापार का महज 15 प्रतिशत है, जबकि ब्रिक्स देशों में दुनिया की कुल आबादी का 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सा बसता है।

श्री मोदी ने हाल ही में भारत में शुरु किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि वह फिटनेस और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच संपर्क और साझेदारी बढ़ाने के इच्छुक हैं।

उन्होंने कहा कि टिकाऊ जल प्रबंधन और साफ सफाई आज भी शहरी क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने इसके साथ ही ब्रिक्स देशों के जल मंत्रियों की पहली बैठक भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा।

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिक्स की रणनीति पर पहली बार संगोष्ठी के आयोजन पर खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद जताई कि पांच कार्य समूह के प्रयास और गतिविधियां आतंकवाद और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि वीजा, सामाजिक सुरक्षा समझौतों और योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पांच सदस्य देशों के बीच व्यापार और पर्यटन के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी।

विश्व की आर्थिक वृद्धि में ब्रिक्स देशों का 50 प्रतिशत योगदान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 नवंबर को ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित किया। अन्य ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने भी व्यापार मंच को संबोधित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विश्व की आर्थिक वृद्धि में ब्रिक्स देशों का योगदान 50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को गति दी, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में नई सफलताएं हासिल कीं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों के अंदर व्यापार और निवेश के लक्ष्य और अधिक महत्वाकांक्षी होने चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार की लागत को कम करने के लिए ब्रिक्स देशों से सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तक कम से कम पांच ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त उपक्रम का गठन किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पूर्वानुमान योग्य नीति और व्यापार के अनुकूल सुधारों की वजह से भारत विश्व की सबसे खुली और निवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था है।

500 अरब डॉलर के आपसी व्यापार का लक्ष्य

प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स व्यापार परिषद् और नव विकास बैंक-एनडीबी के साथ ब्रिक्स नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ब्रिक्स व्यापार परिषद् ने अगले शिखर सम्मेलन तक ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच 500 अरब डॉलर के आपसी व्यापार का लक्ष्य हासिल करने की रूपरेखा तय की है। उन्होंने कहा कि नव विकास बैंक और ब्रिक्स व्यापार परिषद् के बीच साझेदारी समझौता दोनों ही संगठनों के लिए लाभदायक रहेगा।

श्री मोदी ने ब्रिक्स देशों और नव विकास बैंक से प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में सक्षम अवसंरचनाओं के निर्माण की वैश्विक पहल में साथ आने की अपील की। साथ ही, उन्होंने भारत में नव विकास बैंक की क्षेत्रीय शाखा खोले जाने का काम जल्दी पूरा करने का भी अनुरोध किया, ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में परियोजनाओं को बढ़ावा मिल सके।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि ब्रिक्स आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का हमारा सपना परिषद् और नव विकास बैंक के पूरे सहयोग से ही साकार हो सकता है।''

ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोलसोनारो से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रासीलिया में 13 नवंबर को ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जेयर मेसियस बोलसोनारो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का निमंत्रण स्वीकार किया।

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देश इस मौके पर रणनीतिक साझेदारी को व्यापक रूप से बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वह व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ब्राजील से कृषि उपकरण, पशुपालन, फसल कटाई

के बाद की प्रौद्योगिकी और जैव ईंधन सहित कई क्षेत्रों में संभावित निवेश की रूपरेखा भी तैयार की।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बताया कि उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भारत जाएगा। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों सहित सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति के फैसले का स्वागत किया।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्रासीलिया में 13 नवंबर को चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने चेन्नई में दूसरी अनौपचारिक बैठक में उनकी मेजबानी करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की प्रशंसा की और कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों द्वारा किए गए स्वागत को नहीं भूलेंगे। उन्होंने 2020 में चीन में

तीसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को आमंत्रित किया।

चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने व्यापार और निवेश से संबंधित मामलों पर संवाद बनाए रखने के महत्व पर सहमति जताई। राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को शंघाई में चीन के निर्यात-आयात प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार और अर्थव्यवस्था पर नए उच्च स्तरीय तंत्र के शीघ्र विकसित करने पर सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने अगले साल दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारियों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने कहा कि इससे लोगों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि सीमा से संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की एक और बैठक होगी। दोनों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स और आरसीईपी जैसे बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार साझा किए।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर ब्रासीलिया में 13 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस साल दोनों नेताओं की यह चौथी मुलाकात है।

बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की व्लादिवोस्तोक यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हमारे रक्षा मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री की रूस की सफल यात्राओं का विशेष रूप से उल्लेख किया।

दोनों नेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार का 25 अरब डॉलर का लक्ष्य पहले ही हासिल किया जा चुका है। दोनों नेताओं ने फैसला किया कि क्षेत्रीय स्तर पर व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए रूसी प्रांतों और भारतीय राज्यों के स्तर पर अगले साल एक द्विपक्षीय क्षेत्रीय मंच का आयोजन किया जाएगा।

दोनों नेताओं ने तेल और प्राकृतिक गैस के आयात में स्थिरता और प्रगति का उल्लेख किया। राष्ट्रपति श्री पुतिन ने प्राकृतिक गैस में आर्कटिक क्षेत्र की क्षमता पर प्रकाश डाला और भारत को इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

दोनों नेताओं ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में खासकर नागपुर-सिकंदराबाद रेल लाइन की गति बढ़ाने के संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा की। नेताओं ने रक्षा क्षेत्र और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने तीसरे देशों में असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग की संभावनाओं का स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों पक्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समान विचार रखते हैं और भविष्य में भी परामर्श जारी रखा जाएगा। राष्ट्रपति श्री पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अगले साल विजय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मास्को आने का निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ■

सरकार ने स्टार्ट-अप, एमएसएमई के लिए पेटेंट व्यवस्था को सरल बनाया है: पीयूष गोयल

भारत जैव प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग गठित करने वाला विश्व का पहला देश

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्टार्ट-अप, एमएसएमई से संबंधित पेटेंट व्यवस्था को सरल बनाया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि औद्योगिक विभाग जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए और उभरते हुए उद्यमों को सभी प्रकार का प्रोत्साहन देगा। श्री गोयल 22 नवंबर को नई दिल्ली में ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019 में पुरस्कार वितरित करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।

श्री गोयल ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र है। उन्होंने कहा, "न्यू इंडिया के प्रधानमंत्री के विजन और डीबीटी के प्रयास आपस में जुड़े हुए है।" उन्होंने कहा कि 1.3 अरब भारतीयों की आकांक्षाएं प्रौद्योगिकी व नवाचार को अपनाने की हमारी सफलता पर निर्भर हैं, जिसके आधार पर परिवर्तन होते है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी का एक अलग विभाग गठित करने वाला विश्व का पहला देश है। अमेरिका को छोड़कर एफडीए द्वारा अनुमोदित दवाओं की सबसे बड़ी संख्या (523) भारत से हैं।

उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग वर्तमान में भारत में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य का है। डीबीटी का लक्ष्य 2025 तक 7 लाख करोड़ रुपये का है। विश्लेषकों का कहना है कि यह 11 लाख से 12 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को छू सकता है। शिक्षा जगत, उद्योग जगत और सरकार को एक साथ आने का आह्वान करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दीर्घावधि, नवाचार का आदर्श होना चाहिए। श्री गोयल ने जीबीआई पुरस्कार प्रदान किये, विभिन्न रिपोर्टें जारी की और बीटी स्टार्ट-अप्स के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। ■

नितिन गडकरी ने नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया

केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 27 नवंबर को हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया।

श्री गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन प्रणाली तथा ई-मोबिलिटी जैसे प्रासंगिक विषयों पर सम्मेलन के आयोजन के लिए आईसीएटी को बधाई दी। उन्होंने कृषि क्षेत्र को ऑटोमोबिल क्षेत्र से जोड़ने के महत्व को दोहराया और कहा कि जैव डीजल, कृषि तथा ऑटो इंडस्ट्री का भाग्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि जैव डीजल के लिए अखाद्य तेल के उत्पादन से देश के कृषि आधार को समर्थन दिया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ऑटोमोटिव उद्योग को महत्वपूर्ण मानती है और कारगर नीतियों से उद्योग को समर्थन देना चाहती है।

इस अवसर पर आईसीएटी के निदेशक श्री दिनेश त्यागी ने कहा कि आईसीएटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों की श्रृंखला में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन 2019 पहला है। श्री त्यागी ने कहा कि इससे देश में 125 वर्षों से उपयोग किए जाने वाले आईसी ईंजन का उचित विकल्प पाने में लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर फोकस है। नुजेन जेनरेशन मोबिलिटी, हरित, सुरक्षित तथा किफायती होगी।

सम्मेलन में लाइव टेस्ट डिमॉन्सट्रेशन, प्रशिक्षण सत्र, पैनल, चर्चा तथा टेस्ट ट्रैक डिमॉन्सट्रेशन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन में कनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन आईसी ईंजन जैसी भविष्य की वाहन टेक्नोलॉजी दिखाई गई।

गौरतलब है कि सम्मेलन के विषयों में ई-मोबिलिटी, हाइड्रोमोबिलिटी, कनेक्टेड व्हीकल तथा आईटीएस शामिल किए गए। ■

चिकित्सा बीमा पालिसी खरीदने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी में वृद्धि

पिछले कुछ समय में चिकित्सा बीमा खरीदने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में चिकित्सा बीमा खरीदारों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज नौ प्रतिशत थी जो वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 19 प्रतिशत पर पहुंच गयी।

बीमा संबंधी ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अब हर 10 में से छह महिलायें अपने लिये चिकित्सा बीमा खरीद रही हैं और ये महिलायें पांच लाख रुपये या इससे अधिक का प्लान चुन रही हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार चिकित्सा बीमा खरीदने वाली महिलाओं की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में 57 प्रतिशत बढ़ी है। इस दौरान पांच लाख से 10 लाख रुपये तक का प्लान खरीदने वाली महिलाओं की संख्या 80 प्रतिशत तथा 10 लाख रुपये से अधिक का प्लान खरीदने वाली महिलाओं की संख्या 61 प्रतिशत बढ़ी है। ■

प्रधानमंत्री ने श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 नवंबर को श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, 'यह दिन गुरुनानक देव जी के न्याय संगत, समग्र और सौहार्दपूर्ण समाज के स्वप्न को पूरा करने के लिए खुद को एक बार फिर समर्पित करने का दिन है।' ■

मूल्यपरक शिक्षा और सतत विकास लक्ष्य

रमेश पोखरियाल 'निशंक'

सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को परिवार माना है। 'अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम।' संपूर्ण दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का महान विचार लेकर भारत देश ने 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः' की परिकल्पना को स्वीकार करते हुए संपूर्ण मानवता के कल्याण की प्रार्थना की है। हमारा चिंतन, हमारे दर्शन और हमारे मूल्यों में एक ही भावना परिलक्षित होती है कि संसार में कोई कष्ट में न रहे। एकात्म मानववाद का चिंतन कर हमने समाज में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिया है। पिछड़े, दलित, उपेक्षित वर्ग तक पहुंचना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

विश्व बंधुत्व, सामाजिक समरसता, सौहार्द, परोपकार, सहिष्णुता, प्रेम की भावना को हम शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने और पुष्पित पल्लवित करने में सक्षम हैं। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम समग्र विकास की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। विश्व में शीर्ष पर रहने का श्रेय हमें शिक्षा के माध्यम से ही मिला। विश्व गुरु भारत पुरातन काल में ज्ञान और विज्ञान का नेतृत्व केवल इसलिए कर पाया क्योंकि उसकी शिक्षा सर्वोत्कृष्ट मूल्यों पर आधारित थी। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। सदैव से ही भारत अपनी मूल्यपरक शिक्षा द्वारा वैश्विक कल्याण के साझा उद्देश्यों को साकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाता रहा है। आज के चुनौतीपूर्ण वातावरण में भारत विश्व का तीसरा बड़ा शिक्षा तंत्र होने के नाते तैंतीस करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए कृत संकल्पित है। देश में एक हजार से ज्यादा विश्वविद्यालय और पैंतालीस हजार से ज्यादा डिग्री कालेज हैं।

सतत विकास के तीन स्तंभ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण स्थिरता और विकास संतुलित करने पर केंद्रित है। मुझे लगता है कि हमें अपने छात्रों को यह सिखाना होगा कि स्थिरता केवल पर्यावरण के बारे में ही नहीं है, बल्कि हमें समग्र विकास के विषय में सोचना है। एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कार्यों से प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस बारे में प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ना है। 'स्थिरता' की परिभाषा से अपने विद्यार्थियों को अवगत कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यही कारण था कि जहां हमने अपने परिसरों में सिंगल यूज

सतत विकास के तीन स्तंभ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण स्थिरता और विकास संतुलित करने पर केंद्रित है।

प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, वहीं 'एक पेड़ एक छात्र' अभियान चला कर अपने परिसरों को हरित परिसर बनाने का प्रयास किया है। हम शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति के निर्माण के अपने मूल जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मुझे लगता है कि युगों-युगों से चली आ रही हमारी शिक्षा पद्धति हमारा दर्शन, हमारा चिंतन और हमारा भाव- सब कुछ मानवता के कल्याण के लिए केंद्रित रहता है। 'असतो मा सदगमयः' असत्य से सत्य की ओर एवं 'तमसो मा ज्योर्तिगमयः' अंधकार से प्रकाश की ओर प्राणी मात्र को ले जाने के लिए हम संकल्पित हैं।

हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक बच्चे और नागरिक को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। हम समग्र शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कर समस्त भारत में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। तैंतीस वर्षों के अंतराल में हम देश के शैक्षिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली नई शिक्षा नीति लाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारी नई शिक्षा नीति गुणवत्तापरक, रोजगारपरक है, नवचारयुक्त, कौशलयुक्त है, सामाजिक सरोकारों से युक्त है, व्यावहारिक और शोधपरक है और पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाली है।

भारत विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक लोकतांत्रिक परामर्श अभियान से नई शिक्षा नीति को कार्य रूप देने की ओर गतिशील है। लगभग सवा दो लाख लोगों के सुझाव इस बात का परिचायक हैं कि हमने शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारकों तक पहुंचने का प्रयास किया है। विद्यार्थी, अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन, प्रशासक, नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि एवं गैर सरकारी संगठनों समेत हमने हर वर्ग तक पहुंचने में सफलता पाई है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह नीति सफल साबित होगी। हमारा लक्ष्य है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शिक्षा को नवाचार युक्त गुणवत्तापरक बनाया जाए। भारत उच्च शिक्षा नीति को गुणात्मक एवं वहनीय बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

स्वयं पोर्टल के माध्यम से हम भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशी छात्रों को भी निशुल्क उच्च शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं। भारत के ही एक करोड़ तेईस लाख छात्र स्वयं पोर्टल के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विज्ञान भारती एवं 'आरोग्य भारती' के

माध्यम से हम ज्ञान के भंडार को निशुल्क बांटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ हमारा इस संबंध में समझौता हो चुका है। समूचे विश्व के छात्र भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 'स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम' के तहत भारत की सौ से ज्यादा सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाएं विश्व भर में छात्रों के लिए आकर्षक शिक्षा केंद्र के रूप में उपलब्ध हैं।

शिक्षा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करना हमारी प्राथमिकता है। भाषा राष्ट्र की अभिव्यक्ति है और भाषा के बगैर राष्ट्र गूंगा है। भाषा के महत्त्व को समझते हुए नई नीति के माध्यम से हम देश की हिंदी, संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित, पुष्पित एवं पल्लवित करने में जुटे हैं।

भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। मानव सभ्यता हमारी आधुनिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग करती है। मानव इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां सभ्यता ने विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। हमें क्षति और विनाश से बचाते हुए इस बात को ध्यान में रखना है कि हम प्राकृतिक दुनिया के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं।

ब्रिटिश काल के दौरान शुरू हुई मूल्यों की गिरावट लंबे समय तक जारी रही। यह हमारा सौभाग्य रहा कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे सिद्धांतों और मूल्य युक्त नेतृत्व ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के अपने शक्तिशाली मूल्यों के साथ भारत को अपनी ताकत वापस पाने में मदद की। आजादी के सत्तर वर्षों के बाद प्रभावी प्रबंधन और अस्तित्व के लिए इन मूल्यों पर वापस जाने की आवश्यकता है।

मानवता के लिए शिक्षा को संयुक्त रूप से बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की अनूठी पहल को साकार करने के लिए एवं मानवता के लिए शिक्षा को संयुक्त रूप से बदलने के लिए मैं वैश्विक साझेदारी की आशा करता हूं। आज हम परिवार के अंदर बंट गए हैं, खुद को कंप्यूटर तक सीमित कर लिया है और स्मार्टफोन को अपनी दुनिया बना लिया है। इन जंजीरों से निकलने में बापू के विचार हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

आज के युग में भारत इस तरह की पहल शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जल और स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिल कर करना चाहता है। मैं सभी सम्मानित देशों से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिल कर के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करें। ■

(लेखक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। यह लेख यूनेस्को में दिए उनके भाषण का अंश है।)

(जनसत्ता से साभार)

'कुल्हड़ चाय' की सोंधी खुशबू से महकेंगे राजस्थान के अनेक रेलवे स्टेशन

'कुल्हड चाय' की सोंधी खुशबू जल्द ही राजस्थान के अनेक रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली है। जिन रेलवे स्टेशनों के यात्री इस चाय का लुत्फ उठा सकेंगे उनमें बीकानेर, सिरसा, भिवानी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, सूरतगढ़, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, भगत की कोठी, लूनी, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, गांधी नगर, दुर्गापुरा, सीकर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही रोड और आबू रोड आदि शामिल हैं।

इससे पहले केन्द्रीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) मंत्री श्री नितिन गडकरी के अनुरोध पर केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने रेलवे बोर्ड को इस संबंध में निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने पिछले वर्ष केन्द्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया था कि प्लास्टिक के बर्तनों के स्थान पर कुल्हड़ और मिट्टी के अन्य बर्तनों का उपयोग करने के लिए एक पायलट परियोजना के तहत वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्टेशनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इस परियोजना के लिए अनुमति दी गई और संबंधित डीआरएम द्वारा पेश की गई इन दो रेलवे स्टेशनों से जुड़ी 6 माह की रिपोर्ट अत्यंत उत्साहवर्धक पाई गई।

श्री वी.के. सक्सेना ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा, 'यह प्लास्टिक के उत्पादों के स्थान पर मिट्टी से बने उत्पादों का उपयोग करने के लिए उत्तर-पश्चिमी रेलवे द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग्य कदम है। मिट्टी से बने बर्तनों के बाजार का अभाव होने के कारण देश के कुम्हारों को अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य छोटे कार्यों को अपनाना पड़ रहा है। इसमें बड़ी संख्या में कामगार लगे हुए हैं।

केवीआईसी ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए पिछले वर्ष कुम्हार सशक्तिकरण योजना शुरू की थी और पत्थरों के पुराने चाकों के स्थान पर 10,000 इलेक्ट्रिक चाकों का वितरण किया था। 400 रेलवे स्टेशनों की जरूरतों की पूर्ति के लिए केवीआईसी ने इस वर्ष देश भर में 30,000 इलेक्ट्रिक चाक वितरित करने की योजना बनाई है। 30,000 इलेक्ट्रिक चाकों की मदद से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ तैयार किये जाएंगे। इससे न केवल संबंधित क्षेत्र के कुम्हार समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि पर्यटकों की अच्छी सेहत को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, ट्रैवल एवं पर्यटन उद्योग को अनूठे भारतीय स्वाद का आनंद भी मिलेगा।' ■

साकार हो रहे गरीबों के सपने

नरेन्द्र सिंह तोमर

उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जिले के एक गांव में अमरावती अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रह रही थीं। वह गांव में मजदूरी से होने वाली आमदनी से अकेले ही घर का खर्च चलाया करती थीं। मानसून में उनकी झोपड़ी में बारिश का पानी टपकना आम था। इस दौरान खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी भी कठिनाई से मिलती थी। ऐसे में वह कई बार काम के अवसर भी खो देती थीं। अमरावती के लिए इस तरह की कठिनाइयों के बीच गरिमापूर्ण जीवन बिताना कल्पना से बाहर की बात थी। यह कहानी अकेले अमरावती की ही नहीं है, ऐसे कई लोग और परिवार हैं जिनके लिए पक्के मकान में गरिमापूर्ण जीवन जीने का सपना भी दुर्लभ था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सफल क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अमरावती एवं उनके जैसे 87 लाख से अधिक परिवार जरूरी सुविधाओं से युक्त आवास पाकर आज गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। यह सब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन से संभव हो पाया है।

गरिमापूर्ण जीवन के लिए मूलभूत सुविधाएं होना जरूरी

शौचालय, एलपीजी सिलेंडर के साथ बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान की उपलब्धता गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए पूर्व की इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में आगरा से 20 नवंबर, 2016 को इसका शुभारंभ किया। इसका तात्कालिक उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 के बीच पहले चरण के अंतर्गत एक करोड़ मकानों का निर्माण करना था। बाकी एक करोड़ 95 लाख मकानों को दूसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है। सभी राज्य सरकारों की भागीदारी से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब तक 87 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है।

बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान होने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है

यह सच है कि पानी, रसोई गैस, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान का होना किसी भी परिवार का आत्मसम्मान बढ़ाता है, क्योंकि इससे उस परिवार को दिन-प्रतिदिन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह अधिक समय आर्थिक गतिविधियों के लिए निकाल पाता है। परिणामस्वरूप उस परिवार को और अधिक आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। नवनिर्मित मकानों से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हम ये मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिये उपलब्ध करा रहे हैं।

सत्यापन प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों की पहचान की गई

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले सरकार ने आवास विहीनता के मानदंडों पर आधारित सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के जरिये लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया। इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई। इससे इस योजना के लाभार्थियों के चयन और स्थाई प्रतीक्षा सूची में पूर्ववर्ती क्रम के अनुसार मकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने में मदद मिली।

लाभार्थियों के खातों में धनराशि को भेजने से भ्रष्टाचार रुका

सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में धनराशि को सीधे भेजने से भ्रष्टाचार रोकने में भी सफल हुई है। इस योजना में निगरानी प्रक्रिया साक्ष्य-आधारित है। भुगतान करने से पहले आवास एप के जरिये निर्माण के पूर्व निर्धारित स्तरों के चित्र लिए जाते हैं। फिर इन जियो टैग्ड चित्रों को समय और तारीख के साथ आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है। ये विवरण सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। इससे वित्तीय अनुशासन कायम हुआ है। हम घर बैठे देश के किसी कोने में निर्मित हो रहे आवास की वास्तविक प्रगति से अवगत हो सकते हैं।

मकानों के निर्माण में तेजी आई

इस योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एकल नोडल खाता खोलने और संचालित करने की भी रही। पलानी ग्रामीण आवास योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक और उप-ब्लॉक के स्तर पर विभिन्न खाते होते थे। उनमें अनावश्यक रूप से पैसे पड़े रहते थे। पात्र लाभार्थियों को फंड जारी नहीं हो पाते थे। नतीजतन मकान निर्माण में देरी होती थी। एकल नोडल खाता प्रणाली से इस समस्या का समाधान हो गया है। इस खाते से राज्य के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जा सकती है। इससे धनराशि का सुचारू प्रवाह

सुनिश्चित हुआ है और मकानों के निर्माण में तेजी आई है।

प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसर भी बढ़े

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने और ग्रामीण आवास के निर्माण की सभी जरूरतों को एक ही जगह पर पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत न केवल राजमिस्त्री से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि बार-बेंडिंग और शटरिंग इत्यादि का काम भी सिखाया जाता है। इससे इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलने के अवसर भी बढ़े हैं। इस कार्यक्रम के तहत कुल 53,370 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित भी किया जा चुका है। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से मकान का निर्माण पूरा करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या भी घटी है।

आवास प्लस मोबाइल एप पर पात्र उम्मीदवारों की सूची को अपडेट किया जाता है

2015-16 में किसी मकान का निर्माण कार्य पूरा होने में औसतन 314 दिन लगते थे जो वर्ष 2017-18 में घटकर 114 दिन रह गए। इससे वार्षिक आधार पर पूरे किए जाने वाले मकानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के क्रियान्वयन के दौरान सरकार को ऐसे परिवारों के बारे में पता चला जो संभवतः पात्र हैं, लेकिन वे स्थाई प्रतीक्षा सूची में किसी कारण शामिल नहीं हो पाए। ऐसे छूटे हुए परिवारों का विवरण दर्ज करने के लिए आवास प्लस मोबाइल एप विकसित किया गया। इनसे मिले आंकड़ों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की सूची को अपडेट किया जा रहा है।

मोदी सरकार 2022 तक करेगी गरीबी मुक्त नए भारत का सपना पूरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2022 तक गरीबी मुक्त नए भारत का सपना पूरा करने जा रही है और इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से हर पात्र लाभार्थी को मार्च, 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। ■

(लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं)
(साभार दैनिक जागरण)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विधेयक 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोग लाभान्वित होंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान 20 नवंबर को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक से दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराने में मदद मिलेगी। उन्हें संपत्तियों के पंजीकरण और स्टैम्प शुल्क में भी रियायत मिलेगी।

दिल्ली में सरकारी और निजी भूमि पर बनी अनाधिकृत कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों में जमीन या बने हुए मकान का मालिकाना हक आमतौर पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, एग्रीमेंट टू सेल तथा पेमेंट एंड पोजेशन दस्तावेज के आधार पर मिला हुआ है। इन कॉलोनियों में अचल संपत्तियां, पंजीकरण प्राधिकरणों द्वारा पंजीकृत नहीं है। ऐसे में इनमें रहने वालों को इन संपत्तियों के मालिकाना हक का कोई टाइटेल डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी संपत्तियों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी तरह की ऋण सुविधा नहीं दी जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी (सी) 13917 में 2009 के सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हरियाणा सरकार और अन्य के मामले में 11 अक्टूबर, 2016 को सुनाए गए फैसले में कहा था कि सेल एग्रीमेंट/जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या विल ट्रांजेक्शन को किसी भी संपत्ति का वैधानिक तौर पर हस्तांतरण या बेचा जाना नहीं माना जा सकता और उन्हें एग्रीमेंट ऑफ सेल के रूप में ही माना जाएगा।

सरकार ने इन अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल, पोजेशन लेटर और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने का फैसला किया जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण है। सरकार ने इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास तथा वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को भी बेहतर बनाने का फैसला किया। ■

केन्द्रीय गृह मंत्री ने लद्दाख के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का उद्घाटन किया

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 17 नवंबर को लद्दाख क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का शुभारंभ किया, जिससे अत्यंत ठंड के मौसम में डीजल ईंधन के जम जाने के कारण लोगों की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पानीपत रिफाइनरी द्वारा पहली बार उत्पादित विंटर ग्रेड डीजल इस क्षेत्र में -33 डिग्री की अत्यधिक सर्दी में भी नहीं जमता, जबकि सामान्य ग्रेड के डीजल के इस्तेमाल में कठिनाई होती है।

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 2014 से लद्दाख क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जो पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित था। संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री शाह ने कहा कि लद्दाख अधिनियम में बदलाव करके स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद को अधिक बजट देने के अलावा अधिक स्वायत्तता भी दी गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय करारोपण की शक्ति मिलने से वे खुद वित्तीय संसाधन भी जुटा पाएंगे।

बिजली के लिए श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन, लेह एवं करगिल के लिए 14 सोलर परियोजनाओं, लद्दाख विश्वविद्यालय, दो नये महाविद्यालयों, दो नये टर्मिनलों, पांच नये टूरिस्ट सर्किटों और पर्यटकों तथा पर्वतारोहियों के लिए ट्रैकों, 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित विमान यात्रा सब्सिडी एवं जिला अस्पताल का उन्नयन सहित जैसे नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये अनेक उपायों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे और वे देश के विकास में एकसमान भागीदार होंगे।

श्री शाह ने कहा कि 9 मेगावॉट पनबिजली परियोजना के अलावा 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली भारत की सबसे बड़ी 7,500 मेगावॉट क्षमता वाली सौर बिजली परियोजना अगले चार वर्षों में पूरी होगी। इससे लद्दाख क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि इस विंटर ग्रेड डीजल से अत्यन्त ठंड के समय पर्यटकों को यात्रा के दौरान आसानी होगी और क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा तथा कुल मिलाकर आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।

लेह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े टूर और टैक्सी ऑपरेटरों एवं आम लोगों ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि डीजल के इस नये वर्जन से इस क्षेत्र में एक नया सवेरा आएगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, लद्दाख से सांसद श्री जामियांग सेरिंग नामग्याल और गृह मंत्रालय तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। ■

बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 नवंबर को बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष श्री बिल गेट्स के साथ बैठक की। श्री गेट्स तीन दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे। इससे पहले इन दोनों की मुलाकात सितंबर में न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान हुई थी।

श्री बिल गेट्स ने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में भारत सरकार की मदद करने के लिए अपने फाउंडेशन की प्रतिबद्धता दोहराई।

श्री गेट्स ने पोषण को एक प्रमुख केंद्रित क्षेत्र के रूप में प्राथमिकता देने तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। उन्होंने कुछ नए विचार भी प्रस्तुत किए जो विशेष रूप से पहुंच सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि और प्रणालियों के प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने में मदद कर सकते है, ताकि गरीब और सीमांत लोगों का उत्थान हो सके।

प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार किस प्रकार उनके फाउंडेशन की विशेषज्ञता और जवाबदेही को महत्व देती है। उन्होंने सुझाव दिया कि डेटा और साक्ष्य आधारित विचारशील उपाय और विकसित भागीदारों

की सहायता, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में कार्य की गति बढ़ाने में मदद कर सकती है। ■

प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई में भारत सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 20 नवंबर को प्रत्येक मामले पर गौर करते हुए प्रबंधन नियंत्रण को बरकरार रखते हुए चुनिंदा सीपीएसई (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में भारत सरकार की चुकता शेयर पूंजी को घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसके तहत सरकारी हिस्सेदारी के साथ-साथ सरकार के नियंत्रण वाले संस्थान की अंशभागिता को भी ध्यान में रखा जाएगा।

लाभ : इसका मुख्य उद्देश्य चुनिंदा सीपीएसई में विनिवेश विंडो के दायरे का विस्तार करना है। इससे बड़ी संख्या में लोगों के बीच राष्ट्र की संपदा का विस्तार करने, सीपीएसई में सरकारी निवेश के सक्षम प्रबंधन को बढ़ावा देने, ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राष्ट्र के आर्थिक विकास की गति तेज करने में सीपीएसई के योगदान को बढ़ाना जैसे विनिवेश के उद्देश्यों की पूर्ति में भी मदद मिलेगी।

इससे बाजार में मुक्त रूप से उपलब्ध शेयरों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे भारतीय पूंजी बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर सकारात्मक असर हो सकता है। इसके अलावा छोटे (रिटेल) और संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की गुंजाइश बढ़ाने पर भी सकारात्मक असर हो सकता है। यही नहीं, इससे निवेशकों की संभावित सकारात्मक धारणा की बदौलत सीपीएसई का बाजार प्रीमियम भी बढ़ सकता है। ■

'राज्य और केन्द्र प्रतिद्वंद्वी न होकर प्रतिभागी या सहभागी हैं'

भारत के संसदीय इतिहास में राज्यसभा की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 नवंबर को कहा कि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र प्रतिद्वंद्वी न होकर प्रतिभागी या सहभागी हैं। यह सदन राज्यों के विकास में अपनी भूमिका निभा रहा है।

श्री मोदी ने उच्च सदन के 250 वें सत्र के अवसर पर ''भारतीय राजनीति में राज्यसभा की भूमिका ...आगे का मार्ग" विषय पर हुई विषेष चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस सदन ने कई ऐतिहासिक पल देखे हैं और कई बार इतिहास को मोड़ने का भी काम किया है।

उन्होंने राज्यसभा के 200वें सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए संबोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी द्विसदनीय संसद है। किंतु राज्यसभा को कभी ''गौण" सदन बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि हमारे इस दूसरे सदन को ''सपोर्टिव (सहयोगात्मक)'' सदन बने रहना चाहिए।

श्री मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण को सदा केन्द्र में रखना चाहिए, किंतु क्षेत्रीय हितों का संतुलन भी बनाये रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संतुलन बनाये रखने का काम सबसे अच्छी तरह से राज्यसभा में ही हो सकता है।

उन्होंने कहा कि यह सदन ''चैक एवं बैलेंस" का काम करता है। किंतु ''बैलेंस और ब्लाक (रुकावट)" में अंतर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ''रुकावट के बजाय संवाद का रास्ता चुनना चाहिए।"

उन्होंने ''स्थायित्व एवं विविधता" को राज्यसभा की दो विशेषताएं बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता की जो ताकत है वह सबसे अधिक इसी सदन में प्रतिबिंबित होती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए ''चुनावी अखाड़ा" पार कर पाना संभव नहीं होता है। किंतु इस व्यवस्था के कारण हमें ऐसे महानुभावों के अनुभवों का लाभ मिलता है।

श्री मोदी ने कहा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं बाबा साहेब अंबेडकर हैं। उन्हें किन्हीं कारण से लोकसभा में जाने का अवसर नहीं मिल सका और उन्होंने राज्यसभा में आकर अपना मूल्यवान योगदान दिया। उन्होंने कहा कि यह सदन ''चैक एवं बैलेंस (नियंत्रण एवं संतुलन)'' का काम करता है। किंतु ''बैलेंस और ब्लाक (रुकावट)'' में अंतर रखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्यसभा सदस्यों को सुझाव दिया कि हमें ''रुकावट के बजाय संवाद का रास्ता चुनना चाहिए।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यसभा के सभी सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं के बीच यह चर्चा चली थी कि सदन एक हो या दो। किंतु अनुभव बताता है कि संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी।

श्री मोदी ने कहा कि इस सदन में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी शासन व्यवस्था में निरंकुशता नहीं आने दी। उन्होंने राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए कहा, ''हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारी सोच ही दो सदनों वाली हमारी संसद के औचित्य को साबित करेगी।''

उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सोचने का विषय है कि डा. राधाकृष्णन ने हमसे जो अपेक्षाएं की थीं, क्या हम उन पर सही उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि इस सदन के कारण उन्हें कई चीजों को नये सिरे से देखने का मौका मिला है। उन्होंने तीन तलाक विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा कि इस सदन ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक परिपक्व कदम उठाया। इसे लेकर पहले कुछ आशंकाएं जतायी जा रही थीं, किंतु वह गलत साबित हुईं।

श्री मोदी ने जीएसटी और सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोगों को आरक्षण संबंधी विधेयकों को पारित करने के लिए भी उच्च सदन की सराहना की। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35 ए के हटाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च सदन ने इस मामले में भी विधेयक पारित कर देश को दिशा दिखायी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राकांपा और बीजद से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनके सदस्य कभी आसन के समक्ष नहीं आते। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों से सत्ता पक्ष सहित सभी दलों को सीख लेनी चाहिए कि हम आसन के समक्ष आये बिना भी अपना राजनीतिक विकास कर सकते हैं। ■

सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हैं तैयार

27 दलों के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 17 नवंबर को बुलायी गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है। 27 दलों के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।

श्री जोशी के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सत्र भी पिछले सत्र जितना ही फलदायी होना चाहिए। उन्होंने श्री मोदी को यह कहते हुए उद्धृत किया, ''सरकार सदनों के नियमों और प्रक्रियाओं के दायरे में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।'' प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सतर्क रखती है। इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह और कई वरिष्ठ विपक्षी नेताओं ने भाग लिया।

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 16 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की। बैठक के बाद श्री बिरला ने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं ने अलग अलग मुद्दों का उल्लेख किया, जिन पर वे 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान सार्थक चर्चा करना चाहते हैं।

उत्तम से उत्तम बहस हो यह आवश्यक है: नरेन्द्र मोदी

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 नवंबर को मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने देश को प्रगति के मार्ग पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि 2019 का यह आखिरी सत्र है और यह बहुत महत्वपूर्ण सत्र भी है, क्योंकि राज्यसभा का यह 250वां सत्र है। 250 सत्रों की अपनी यात्रा का बहुत ही प्रेरक स्मृतियों के साथ राज्यसभा का 250वां सत्र प्रारंभ हो रहा है। उसी प्रकार से इसी सत्र के दरमियान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं। यह संविधान देश की एकता, अखंडता, भारत की विविधता, भारत के सौंदर्य को अपने में समेटे हुए है और देश के लिए वे चालक ऊर्जा शक्ति है। संविधान के 70 साल अपने आप में, इस सदन के माध्यम से देशवासियों के लिए भी एक जागृति का अवसर बन सकता है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों करीब-करीब सभी दल के नेताओं से मिलने का मौका मिला है और यह सत्र भी जैसे पिछली बार नई सरकार बनने के बाद सभी दलों के सहयोग के कारण, सभी माननीय सांसदों के सहयोग के कारण हर किसी की सक्रिय सकारात्मक भूमिका के कारण गत सत्र अभूतपूर्व सिद्धियों से भरा हुआ था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मुझे सार्वजनिक रूप से गर्व से कहना चाहिए कि ये सिद्धि सरकार की नहीं होती है, ये सिद्धि ट्रेजरी बेंच की नहीं होती है, ये सिद्धि पूरे सदन की होती है और सभी सांसद उसके

हकदार होते हैं और इसलिए मैं फिर एक बार सकारात्मक सक्रिय भूमिका के लिए सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं ये सत्र भी देश के विकास की यात्रा को, देश को गति देने में, दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ्य हम हमारी संसद से भी प्रकट करें।

उन्होंने कहा कि हम सभी मुद्दों पर खुलकर के चर्चा चाहते हैं। उत्तम से उत्तम बहस हो ये आवश्यक है। वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, हर कोई अपनी बुद्धि शक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करे और सदन की चर्चा को समृद्ध बनाने में योगदान दें। उससे जो अमृत निकलता है वो देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम आता है। तो इन सभी सांसदों को शुभकामनाएं देते हुए आप सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। ■

देश में शांति, एकता और सदभावना के मूल्य सर्वोपरि हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात 2.0' की छठी कड़ी में 24 नवंबर को कहा कि जब 9 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तो 130 करोड़ भारतीयों ने फिर से ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। देश में शांति, एकता और सदभावना के मूल्य सर्वोपरि हैं।

श्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर जब फ़ैसला आया तो पूरे देश ने उसे दिल खोलकर गले लगाया। पूरी सहजता और शांति के साथ स्वीकार किया। आज 'मन की बात' के माध्यम से मैं देशवासियों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस प्रकार के धैर्य, संयम और परिपक्वता का परिचय दिया है, मैं उसके लिए विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक ओर, जहां लम्बे समय के बाद कानूनी लड़ाई समाप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के प्रति देश का सम्मान और बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सही मायने में यह फैसला हमारी न्यायपालिका के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब देश नई उम्मीदों और नई आकांशाओं के साथ नए रास्ते पर, नये इरादे लेकर चल पड़ा है। नया भारत इसी भावना को अपनाकर शांति, एकता और सदभावना के साथ आगे बढ़े- यही मेरी कामना है, हम सबकी कामना है।

उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को 'विविधता में एकता' का सन्देश देती हैं। 130 करोड़ भारतीयों का ये वो देश है, जहां कहा जाता था कि 'कोस-कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी।' हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही हैं। हालांकि, हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कहीं भाषाएं और बोलियां ख़त्म तो नहीं हो जाएगी! पिछले दिनों मुझे उत्तराखंड के धारचुला की कहानी पढ़ने को मिली। मुझे काफी संतोष मिला। इस कहानी से पता चलता है कि किस प्रकार लोग अपनी भाषाओं, उसे बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहें हैं।

130 करोड़ भारतीयों का ये वो देश है, जहां कहा जाता था कि 'कोस-कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी।'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ख़ास बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 यानी इस वर्ष को 'अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष' घोषित किया है। यानी उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने के कगार पर है। डेढ़-सौ साल

पहले आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने भी कहा थाः

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।"

अर्थात, मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है।

साथ ही, श्री मोदी ने यह भी कहा कि हम सभी देशवासियों को ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब हम अपने वीर सैनिकों को, उनके पराक्रम को, उनके बलिदान को याद तो करते ही हैं, साथ ही योगदान भी करते हैं। सिर्फ सम्मान का भाव इतने से बात चलती नहीं है। सहभाग भी जरुरी होता है और 7 दिसम्बर को हर नागरिक को आगे आना चाहिए। हर-एक के पास उस दिन सशस्त्र सेना का झंडा होना ही चाहिए और हर किसी का योगदान भी होना चाहिए। आइये, इस अवसर पर हम अपनी सशस्त्र सेना के अदम्य साहस, शौर्य और समर्पण भाव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और वीर सैनिको का स्मरण करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को, पर्यावरण को, जल को, जमीन को, जंगल को बहुत अहमियत दी। उन्होंने नदियों के महत्व को समझा और समाज को नदियों के प्रति सकारात्मक भाव कैसे पैदा हो, एक संस्कार कैसे बनें, नदी के साथ संस्कृति की धारा, नदी के साथ संस्कार की धारा, नदी के साथ समाज को जोड़ने का प्रयास ये निरंतर चलता रहा और मजेदार बात ये है कि समाज नदियों से भी जुड़ा और आपस में भी जुड़ा। ■

ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

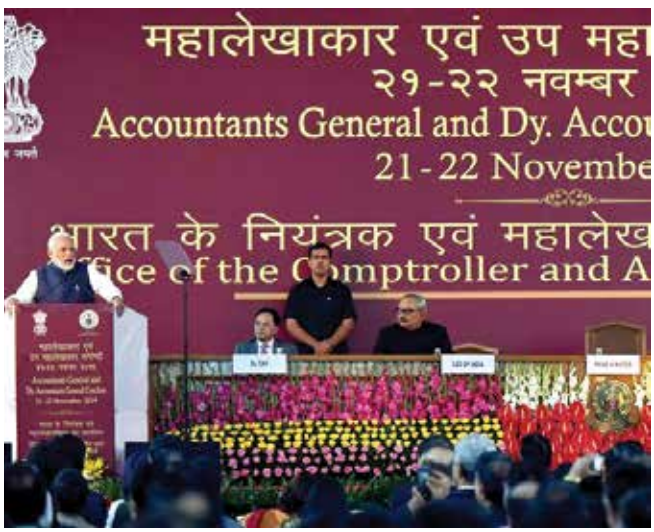

नई दिल्ली में महालेखाकार एवं उप महालेखाकार की बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20